● वर्ष-4
● अंक-59
रायपुर, गुरुवार
17 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6»»» फोटोग्राफी की इन शाखाओं में...

ज्ञानवापी: हिंदू पक्ष ने खुदाई में एएसआई की विशेषज्ञता का हवाला दिया

अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को

वाराणसी । वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने स्थानीय अदालत के समक्ष कहा कि पुरातात्विक चीज़ों की खोज में एएसआई को महारत हासिल है, लिहाज़ा मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे खुदाई कराके ज्योतिर्लिंग के स्थान का सर्वेक्षण कराना चाहिए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जुगल शंभू ने दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 अक्टूबर तय की है। अधिवक्ता यादव ने कहा, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश शंभू के समक्ष अपनी दलील में कहा कि पांच महिला वादियों के मामले में एएसआई सर्वेक्षण की कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को खोदाई कार्य में विशेषज्ञता हासिल है।

उन्होंने दलील देते हुए कहा कि वाराणसी में सारनाथ और राजघाट की खोदाई एएसआई ने ही की है तथा यहां तक कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई भी एएसआई ने ही की थी। यादव ने कहा, इसी आधार पर ज्ञानवापी की भी 4×4 फुट खोदाई की जानी चाहिए और ज्ञानवापी के केंद्रीय गुंबद के नीचे ज्योतिर्लिंग के स्थान का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। उनके मुताबिक, उम्मीद है कि अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अदालत के समक्ष अपनी दलील पेश करेगा। पिछली आठ अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कथित तौर पर अदालत के समक्ष दलील दी थी कि जब हिंदू पक्ष ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आगे बढ़ाने की अपील की है तो निचली अदालत में इस मामले पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि जब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण एक बार पहले हो चुका है तो दूसरा सर्वेक्षण कराने का कोई औचित्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने यह भी कहा था कि सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में गड्ढा खोदना किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है और इससे मस्जिद को नुकसान हो सकता है। इससे पहले, हिंदू पक्ष ने तर्क दिया था कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित मस्जिद के गुंबद के नीचे ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान मौजूद था। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा था कि अर्घे से भौगोलिक जल निरंतर बहता था जो ज्ञानवापी कुंड में एकत्र होता था।

धान खरीदी 14 नवम्बर से 31 जनवरी तक

साय केबिनेट का फैसला

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रूपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी।

विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है.

राज्य कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे यह मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 3.9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और यह बढ़ोतरी इस साल एक अक्टूबर से प्रभावी होगी। सीएम साय ने कहा कि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, इसलिए सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे यह केंद्र सरकार के बराबर हो जाएगा। इस साल मार्च की शुरुआत में साय सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह मूल वेतन का 46 प्रतिशत हो गया था।

ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी तथा अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।

देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने हेतु उत्पाद शुल्क चिपकने वाला लेबल (होलोग्राम) में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।

नीतीश के साथ फिर गठबंधन के सवाल पर बोले तेजस्वी

अब सवाल ही नहीं, उनका समय खत्म हो गया है

नई दिल्ली। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया और दावा किया कि थके हुए जदयू अध्यक्ष के लिए समय आ गया है। जनवरी में जब कुमार अचानक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में लौट आए तो यादव को उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में दिन-ब-दिन कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर डालें तो...ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जहां हत्या, लूटपाट, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराध नहीं होते हों।

राजद नेता ने दावा किया कि बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है, जांच शून्य होती है, पीड़ित परिवार को कभी न्याय नहीं मिलता और आरोपी छूट जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह हो गई है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थक चुके हैं, उनकी स्थिति हम देख सकते हैं। बांका जिले में पत्रकारों से बात करते हुए, राजद नेता ने उन्हें चुनौती दी कि वे केंद्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जाति जनगणना करवाएं, साथ ही राज्य के लिए विशेष दर्जा और हाल की बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज भी हासिल करें।

एक सवाल के जवाब में, अब विपक्ष के नेता, यादव ने कहा अब नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। उनका समय समाप्त हो गया है। वह थक गए हैं और अब बिहार पर शासन करने में सक्षम नहीं हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित 27वें वन खेलकूद महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने यादव को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके खेल कौशल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है।

प्रमुख समाचार

कांटों भरा ताज है, अल्लाह मदद करे; फारूक अब्दुल्ला

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कुछ निर्दलियों को साथ लेकर लगभग अपने दम पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह सरकार बनाई है। फिर भी उमर अब्दुल्ला की शपथ के बाद उनके पिता फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने बेटे को मिली सीएम पद की कुर्सी को कांटों भरा ताज बताया है। उन्होंने कहा कि यह 'कांटों का ताज' है और अल्लाह लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में उनकी मदद करे। अपने दादा से प्रेरणा लेते हुए उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर अब्दुल्ला ने कहा कि नई सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य का दर्जा बहाल करना है। फारूक अब्दुल्ला ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहा, राज्य चुनौतियों से भरा है और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार वही करेगी जो उसने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था। यह कांटों का ताज है और अल्लाह उन्हें (उमर को) सफलता दिलाए और वह लोगों की उम्मीदों को पूरा करें। यह मेरा संदेश है। जहीर अब्दुल्ला ने कहा, राज्य का दर्जा मिलने के बाद, अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए हमारा असली संघर्ष शुरू होगा। अनुच्छेद 370 हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी।

एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर किया ये बड़ा दावा

मुंबई। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के लिए मतदान की तारीख घोषित करने के एक दिन बाद, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी एकल चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए आज बैठक हुई। कांग्रेस महा विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस नेताओं ने इस सप्ताह की शुरुआत में दावा किया था कि चुनाव में जाने वाली 288 सीटों में से अधिकांश के लिए उसके गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट-बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की स्क्रीनिंग मीटिंग के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि आज कई विषयों पर चर्चा हुई, हमें एक और बैठक की अध्यक्षता करनी होगी। इसके बाद सीईसी की बैठक होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति लोगों से झूठे वादे कर रही है, वे लंबे समय तक सत्ता में थे लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया कोई निर्णय लेकिन अब जब चुनाव आ रहा है तो कैबिनेट ने 200 निर्णय कैसे ले लिए? वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसे लागू नहीं करना है इसलिए वे झूठे वादे कर रहे हैं।

पूर्व सांसद जयाप्रदा को अदालत से राहत

रामपुर। रामपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बुधवार को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। जया के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने संवाददाताओं को बताया कि रामपुर से पूर्व सांसद के खिलाफ 2019 में जिले के स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था। उनके मुताबिक, इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद जया ने नूरपुर गांव में बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन कराया और एक सड़क का उद्घाटन किया। जयप्रदा उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थीं। यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती हैऔर जानें उन्होंने बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने जया को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जया ने अदालत के फैसले के बाद संवाददाताओं से कहा, उन्हें अदालत के निर्णय पर खुशी है। कुछ लोग उन्हें रामपुर आने से रोकने के लिये साजिशें रच रहे हैं लेकिन रामपुर उनका दूसरा घर है और वह बार-बार आती रहेंगी।

वक्फ की जमीन पर बनी है नई संसद... पूर्व सांसद अजमल

नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने यह दावा करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है कि संसद का निर्माण वक्फ भूमि पर किया गया होगा। वक्फ बिल पर जेपीसी को लेकर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आवाजें उठ रही हैं और दुनिया भर में वक्फ संपत्तियों की एक सूची सामने आ गई है। संसद भवन, आसपास के इलाके, वसंत विहार के आसपास के इलाके से लेकर हवाई अड्डे तक का निर्माण वक्फ संपत्ति पर किया गया है। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि लोग यह भी कहते हैं कि हवाई अड्डा वक्फ संपत्ति पर बनाया गया है। यह बुरा है, वक्फ बोर्ड के इस मुद्दे पर वे जल्द ही अपना मंत्रालय खो देंगे। उन्होंने कहा कि मैं 15 साल तक संसद में था और अफवाहें थीं कि संसद वक्फ की जमीन पर बनी है। इसलिए मैं इसकी जांच की मांग कर रहा हूं और अगर ये सच है तो बहुत गलत है। वक्फ विधेयक पर कड़ी असहमति व्यक्त करते हुए अजमल ने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का बहिष्कार किया है।

विमानों में बम की धमकी देने वालों नो फ्लाइट लिस्ट में होंगे शामिल

नई दिल्ली। देशभर में इन दिनों लगातार से एयरपोर्ट और विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां में बढ़ोतरी हो रही है। जो कि केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती के तौर पर बन गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने देशभर के हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों में स्काई मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला लिया है। इस मामले में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट और विमानों में बढ़ते खतरे के आकलन और खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद स्काई मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला लिया गया है। बात अगर पिछले तीन दिनों की करें तो अब तक कुल 12 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता सातवें आसमान पर चली गई है। हालांकि जांच में सभी धमकियां झूठी पाई गई हैं, लेकिन सरकार अब इस मामले में एक्शन मोड पर आती हुई नजर आ रही है। जिसको लेकर बुधवार को गृह मंत्रालय ने फर्जी बम धमकियों पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ चर्चा की। जानकारी के अनुसार BCAS के साथ MoCA के गहन चर्चा में निर्णय लिया गया कि एजेंसियां साथ मिलकर धमकी देने वालों की पहचान कर उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल करने किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा की चर्चाओं में भारत, संकट में आती है सबको याद

वीर सिंह

भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की स्थिति निरंतर अपना विश्वव्यापी वर्चस्व बढ़ा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2023 की रिपोर्ट कहती है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में भूख की स्थिति विकट रूप ले चुकी है। कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट और कई देशों में छिड़े युद्धों को इसका मुख्य कारण बताया गया है। इसकी पुष्टि खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट भी करती है, जिसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 82.8 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे, जो दुनिया की लगभग 9.2 प्रतिशत आबादी के बराबर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, यह संख्या 2015 से निरंतर बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण वैश्विक संकटों के चलते खाद्य प्रणालियों की अस्थिरता है।

कृषि और प्रौद्योगिकी में प्रगति के नए-नए मानक प्राप्त करने के बाद भी भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा वैश्विक चुनौती बनी हुई है। जनसंख्या की अनवरत वृद्धि, आर्थिक असमानताओं, आतंकवाद, भू-राजनीतिक संघर्षों व युद्धों तथा जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक खाद्य प्रणाली और उस पर निर्भर मानवता की खाद्य सुरक्षा संकट में है। दुनिया के गरीब क्षेत्रों और पिछड़े मानव समूहों से लेकर विकासशील क्षेत्रों और यहां तक कि संपन्न क्षेत्रों में भी खाद्य सुरक्षा एक गंभीर और अंतहीन मुद्दा बना हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से एसडीजी-2 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2030 तक विश्व को शून्य भूख (जीरो हंगर) स्थिति में होना चाहिए। लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि शून्य भूख का लक्ष्य एक मृग मरीचिका-सा ही प्रतीत होता है। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया में 67 करोड़ लोग भूख से बिलबिला रहे होंगे।

भुखमरी के साथ कुपोषण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक नई रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में पांच साल से कम आयु के

लगभग 14 करोड़ 90 लाख बच्चे अविकसित और चार करोड़ 50 लाख कमजोर थे। वैश्विक स्तर पर दो अरब से अधिक लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से ग्रस्त हैं। कुपोषण का दूसरा रूप है मोटापा। वर्ष 2020 में विश्व भर में पांच वर्ष से कम आयु के तीन करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे।

लगभग एक अरब चालीस करोड़ लोगों का घर, हमारा भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा चर्चाओं में एक कुशल खिलाड़ी की भूमिका में रहता है। कहीं किसी क्षेत्र में कोई खाद्यान्न संकट आता है, तो विश्व भारत से खाद्य आपूर्ति की आस लगाए रहता है। लेकिन खाद्योत्पादन में अग्रणी भारत भूख और कुपोषण से सर्वथा मुक्त नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार, भारत 212 देशों में से 107वें स्थान पर है, जो भूख के गंभीर होने का सूचक है। एफएओ की 'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2023' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग सात करोड़ 40 लाख लोग खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं, और 18 करोड़ 92 लाख लोग, जो कुल आबादी का लगभग 14 प्रतिशत हिस्सा हैं, अल्पपोषण से प्रभावित हैं। भारत में बाल कुपोषण भी एक चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 35.5 प्रतिशत बच्चे अविकसित, 19.3 प्रतिशत कमजोर और 32.1 प्रतिशत कम वजन वाले हैं।

हमारा देश कई खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। आर्थिक असमानताएं, क्षेत्रीय असमानताएं और अपर्याप्त वितरण प्रणालियां तो मुख्य कारण हैं ही, अब जलवायु परिवर्तन का भी प्रवेश हो गया है। भारत अनाज उत्पादन के मोर्चे पर आत्मनिर्भर ही नहीं, निर्यातक देश भी है, जो विश्व के करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का आधार है। लेकिन अपने सभी नागरिकों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के मामले में इसे चुनौतियों?का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लगभग 67 प्रतिशत आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की दुनिया जिस बात के लिए सराहना करती है, वह है कोविड-19 काल से लेकर निरंतर देश के एक बड़े वर्ग को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति। इसके अतिरिक्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन के माध्यम से देश में प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है।

भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है पारिस्थितिकी-केंद्रित सतत कृषि पद्धतियों का विकास। कृषि पद्धतियां ऐसी हों, जिनका संबंध वानिकी से हो और जो मिट्टी, जल व जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करती हों। कुपोषण की समस्या के स्थायी निवारण के लिए ऐसा कृषि प्रबंधन हो, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व खाद्य पदार्थों के माध्यम से लोगों को मिलते रहें। खाद्यान्नों के उचित वितरण के लिए ठोस नीतियों पर आधारित एक उत्तरदायी व्यवस्था विकसित होनी चाहिए।

एसआई भर्ती का रास्ता साफ

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों में परिणाम जारी करने के दिए निर्देश

बिलासपुर। कई महीनों से आंदोलन कर रहे एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के दौरान साल 2018 के अगस्त महीने में कुल 655 पदों के लिए एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) समेत कई अन्य पदों की भर्ती होनी थी। 2019 में सरकार भी बदल गई लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसके बाद राज्य की नई सरकार (कांग्रेस) ने साल 2021 के अक्टूबर में 975 पोस्ट के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया था।

एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जून 2022 में शुरू हुई और 8 सितंबर 2023 तक चली। इस दौरान शारीरिक नापजोख जून-जुलाई 2022 में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई, जबकि मुख्य परीक्षा 26 मई से 29 मई 2023 तक हुई। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 से 30 जुलाई 2023 के बीच आयोजित की गई, और अंत में इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 के बीच लिया गया। परीक्षा को पूरा हुए 1 साल से अधिक हो गया, इस बीच एक बार फिर सरकार बदल गई। 2023 में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन अब तक परीक्षा के परीणाम जारी नहीं हुए।

परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, स्वच्छता अभियान और रक्तदान के जरिये कर अभ्यर्थी कई बार रिजल्ट की मांग कर चुके हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है।

एसआई भर्ती परीक्षा का मामला अदालत में पहुंच गया है। 29 जनवरी, 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के बाद, 16 मई, 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इस चयन के बाद, जो अभ्यर्थी मेरिट सूची में नहीं आए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 प्लाटून कमांडर के थे और मेरिट सूची में 20 गुना अभ्यर्थियों का होना आवश्यक था, जबकि सूची में 6,013 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई। 20 मई, 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिलाओं को शामिल करना गलत था, और उनकी जगह पुरुषों को शामिल करने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट के आदेश के पांच महीने बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन और अनशन किया।

आज 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर परीक्षा परीणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम को लेकर राहत मिलेगी या नहीं।

11 एकड़ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

इधर रिपोर्ट दर्ज होते ही अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

■ **8 दलालों के खिलाफ एफआईआर, 6 गिरफ्तार**

बिलासपुर। बिलासपुर निगम सीमा में शामिल खमतराई के लगभग 11 एकड़ शासकीय भूमि में 94 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मामले का खुलासा प्रशासन द्वारा जांच कराने पर हुआ। जांच में पता चला कि उसी सरकारी भूमि में अवैध रूप से रहने वाले मणिशंकर त्यागी ने अन्य लोगों को सरकारी जमीन टुकड़े में बेच दिया है। जांच के बाद अब प्रशासन ने मामले में 8 जमीन दलालों के खिलाफ एफआईआर कराया है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

साल 2019 नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले खमतराई ग्राम पंचायत को बिलासपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया। इससे पहले और बाद में धीरे-धीरे कर यहां 11 एकड़ शासकीय भूमि पर 94 लोगों ने अतिक्रमण कर मकान और दुकान बना लिया। साथ ही ब्राम्हण समाज को आवंटित दो एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। समाज के लोगों ने इसकी शिकायत

निगम कमिश्नर अमित कुमार से की। जिस पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने मामले की जांच कराई, तो पता चला कि मणिशंकर त्यागी नाम के व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान बना ली है।

राजस्व अधिकारियों की जांच में चला कि मणिशंकर त्यागी ने 11 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद उसने 10 रुपये के स्टाम्प में 94 लोगों को टुकड़े कर प्लाट बेच दिए। जांच के बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ढहाने के निर्देश दिए। इस पर दो दिन पहले रविवार को अतिक्रमण विभाग और जोन क्रमांक 7 की टीम ने खमतराई के वार्ड क्रमांक 58 काली मंदिर के पास बिना अनुमति के वाणिज्यिक और आवासीय निर्माण कराने वाले मणिशंकर त्यागी की चार दुकानों और मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। इस मामले में पहले मणिशंकर त्यागी को जमीन और निर्माण संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिया। समय सीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई।

इस मामले में प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिसमें से पुलिस ने शरद यादव निवासी चांटीडीह, संजय जायसवाल चांटीडीह, मधुसूदन राव कुदूदण्ड, श्रीनिवास राव, कुदूदण्ड, परमेश्वर सूर्यवंशी खमतराई, सुक्रीता बाई सूर्यवंशी खमतराई को गिरफ्तार किया है।

तेलंगाना से बेदखल हुए बस्तर के आदिवासियों को सरकार सुरक्षित और उचित बसाहट की व्यवस्था करें : सीपीआई

बीजापुर। भाकपा जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उग्र दमनकारी आंदओलन के दौरान छत्तीसगढ़ छोड़कर तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में रह रहे 27 परिवारों को तेलंगाना वन विभाग ने जमीन और घर से बेदखल कर घरों में तोडफ़ोड़ और पिटाई कर छत्तीसगढ़ बॉर्डर तारलागुडा में लाकर छोड़ा दिया है। तेलंगाना से बेदखल हुए बस्तर के आदिवासियों की, सरकार तत्काल संज्ञान में ले और उनके स्थाई रुप से रहने एवं जीवन निर्वाह के साधनों की भी उचित व्यवस्था करें। सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने इस सारे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव वाली भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी हितों को लेकर गंभीर नही है। वे सिर्फ़ देश के पूंजीवादियों की दलाली कर रही है और यहां के आदिवासियों को नक्सली के नाम से बेदखल कर इनके ज़मीनों को बड़े कार्पोरेट के

हवाले करना चाहती है। यह मौजूदा सरकार कि प्रमुख नीति है जिसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है।

उन्होने बताया कि विगत कई वर्षों पूर्व बस्तर के अंदर भाजपा-कांग्रेस ने मिलकर नक्सली उन्मूलन के नाम से सलवा जुडूम आंदोलन चलाया गया था। इस उग्र दमनकारी आंदओलन से प्रभावित बस्तर के कई आदिवासी परिवार पड़ोसी राज्यों में पलायन कर गए। जिसमें सर्वाधिक आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में लगभग एक लाख से अधिक लोग पलायन कर जंगलों में बस गये और मजदूरी कर अपना जीवनी यापन कर रहे थे। समय-समय पर इन्हें वापस लाने की मांग राजनैतिक दलों द्वारा सरकार से करते आ रहे थे, लेकिन भाजपा कांग्रेस की किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नही दिया। जिसका खामियाजा आज बस्तर के आदिवासी भुगत रहे हैं, उनकी सुध लेने वाले कोई नही उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ की पूंजीवादी परास्त सरकारें यहां के आदिवासियों को उनके ज़मीन छीनने के उद्देश्य से वोट की राजनीति कर सिर्फ़ उन्हे पलायन करने के लिए मजबूर किया है, जिसका सीपीआई कड़ी निंदा करती है। कल तेलंगाना में बस्तर के आदिवासियों के साथ हुए बर्बरता की सीपीआई कड़ी निंदा करती है ।

मनेंद्रगढ़ में 11 हाथियों का दल वन विभाग ने जारी की चेतावनी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ जिले में हाथियों का एक बड़ा दल जंगलों में विचरण कर रहा है। यह दल पिछले कुछ दिनों से 40 से 50 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में घूम रहा है। वन विभाग स्थिति पर नजर बनाए रखा है। ग्रामीणों को जंगलों की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी है।

केल्हारी वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल मनेंद्रगढ़ वन मंडल के केल्हारी वन परिक्षेत्र में 11 हाथियों का दल पहुंचा है। इस बारे में जानकारी देते हुए परिक्षेत्र के रेंजर रघुराज सिंह ने बताया कि उनकी टीम लगातार इस दल की निगरानी कर रहे हैं। हाथियों के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए वन विभाग ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैला रहा है।

ग्रामीणों को दी गई चेतावनी- वन विभाग की तरफ से गांव गांव में मुनादी कराते हुए यह चेतावनी दी जा रही है कि वे जंगल की ओर न जाएं। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वे हाथियों के दल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जंगल के आस-पास जाने से परहेज करें।

बनियाताल के जंगलों में हाथी का विचरण- रेंजर रघुराज सिंह के अनुसार, हाथियों का यह दल फिलहाल कछौड़ बीट के बनियाताल इलाके के जंगलों में विचरण कर रहा है। यहां का घना जंगल हाथियों के लिए उपयुक्त आवासीय क्षेत्र है, जिससे वे यहां काफी आराम से समय बिता रहे हैं।

वन विभाग की सतर्कता- हाथियों के दल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग का अमला तैनात है। विभाग इस बात का विशेष ध्यान रख रहा है कि कोई ग्रामीण या वन्यजीव इस स्थिति में किसी दुर्घटना का शिकार न हो। वन विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा है और हाथियों के दल की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

समय से नहीं आते कार्यकर्ता और सहायिका, बच्चों को लौटना पड़ता घर

■ **नाराज परिजनों ने जड़ा ताला**

बालोद। बालोद जिले के ग्राम भेड़िया नवागांव में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में सहायिका और कार्यकर्ता समय पर नहीं आते, जिससे नाराज पालकों ने आंगनबाड़ी केंद्र में लगा ताला खुलने ही नहीं दिया। मामले की जानकारी अब तक प्रशासन को नहीं है। आंगनबाड़ी के सभी बच्चे घर लौट गए। आंगनबाड़ी खुलने का तय समय जो निश्चित है उसमें बच्चे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नहीं पहुंच पाते। जिसे लेकर पालकों में काफी आक्रोश है।

ग्रामीण चंद्रशेखर भेड़िया ने बताया कि समय रहते बच्चे तो विद्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र के सहायिका और कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं। उन्हें शासन द्वारा सारी सुविधाएं तो दी जाती है, लेकिन बच्चों को समय पर सही शिक्षा नहीं मिल पाती। आंगनवाड़ी केंद्र सीखने और स्वास्थ्य सुधार का एक बेहतरीन माध्यम है, लेकिन लापरवाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वजह से आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक दो कभी भी समय से नहीं खुलता है।

समय से आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुलने की वजह से बच्चे घर लौट गए। पालकों में इस तरह आंगनवाड़ी की अव्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी है। वहीं, ग्रामीण अब प्रशासन तक शिकायत करने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कभी-कभी का यह चल जाता हैस लेकिन रोज-रोज की यही समस्या है तो आखिर हम अपने बच्चों को यहां कैसे भेज सकते हैं। पूरे मामले की जानकारी देने और उनका पक्ष जानने महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन को फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ केस दर्ज

बेमेतरा। बेमेतरा जिले से साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस ने आखिरकार मंगलवार देर शाम को एफआईआर दर्ज कर ली है। विधायक के बेटे कृष्णा साहू पर मारपीट, गाली-गलौज के साथ अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है। अभी तक आरोपी कृष्णा साहू पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूरा मामला 13 अक्टूबर का है। 13 अक्टूबर को साजा थाना क्षेत्र के ग्राम चेचानमेटा में दशहरा कार्यक्रम के दौरान रात 11 बजे आदिवासी युवक मनीष मंडावी के दोस्त राहुल और विधायक पुत्र कृष्णा साहू के बीच विवाद हुआ। जब मनीष ने बीच-बचाव किया, तो विधायक पुत्र ने जातिगत गाली-गलौज करते हुए हाथ के कड़े से मारा। मारपीट में विधायक पुत्र के साथ करीब 10 लोग और थे, जिन्होंने मनीष और उसके दोस्त राहुल पर हमला किया। इसके बाद समाज के लोग कृष्णा साहू के खिलाफ साजा थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच आदिवासी समाज ने न्याय न मिलता देख कलेक्टर और एसडीएम से इसकी शिकायत की थी।

लापरवाह शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित

सुकमा। शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला ढोंढरा में पदस्थ शिक्षक एलबी जाकिर खान को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सम्बन्धित शिक्षक के संबंध में प्राप्त शिकायत स्कूल में हस्ताक्षर उपरांत शाला से नदारद रहना, अध्यापन कार्य नियमित नहीं करने, दैनंदनी संधारण नहीं करने व मद्यपान कर संस्था में उपस्थित रहते हुए कार्यरत सहकर्मियों व छात्रों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत नहीं किए जाने की पुष्टि कोंटा बीईओ के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में हुई है। जाकिर खान शिक्षक एलबी शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला ढोंढरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय बीईओ कार्यालय कोंटा होगा।

40 लाख की ठगी मामले में कांग्रेस नेता समेत 2 गिरफ्तार

बलौदाबाजार। वीआईपी कोटे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर कसडोल पुलिस ने मामला दर्ज किया और 24 घंटे के भीतर आरोपी यूथ कांग्रेस जिला महासचिव राज गायकवाड़ और उसके साथी दीपराज गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि बीती रात कसडोल के खर्चे निवासी चंद राम यादव ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उसके बेटे का जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिला के नाम पर रायपुर के दो लोगों ने 40 लाख रुपए ले लिया है, जिसमें दस लाख रुपए नगद व तीस लाख रुपए ऑनलाइन भुगतान किया गया है। पैसे लेने के बाद से एक साल से घुमाया जा रहा है। एएसपी ने बताया, आरोपी दीपराज गायकवाड़ व यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव राज गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में कसडोल थाना प्रभारी रितेश मिश्रा सहित स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

पारिवारिक विवाद में चाचा भतीजे में खून-खराबा

धमतरी। जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, हत्या, चोरी और चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ताजा हत्या का मामला भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम भठेली से आया है, जहां मामूली विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बिहारी लाल ढिढी और उसके भतीजे शीत कुमार के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। वहीं आज सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच फिर बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी शीत कुमार ने गुस्से में आकर लोहे के पट्टे से अपने चाचा के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे बिहारी लाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही भखारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

अज्ञात चोरों ने नकदी रकम समेत चोरी किए जेवरात

रायगढ़। रायगढ़ जिले में एक बार फिर से अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर नकदी रकम समेत सोने के जेवरात पर हाथ साफ किया है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौहाकुंडा निवासी दिनेश कुमार त्रिपाठी अपने परिवार के साथ नौ अक्तूबर को ओडिशा गया था। दिनेश ने बताया कि इसी बीच 11 अक्तूबर की सुबह आठ बजे पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनके घर के सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इस सूचना के बाद तत्काल वह रायगढ़ पहुंचा तो देखा कि घर के सामने गेट में लगा ताला टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दिनेश ने बताया कि घर के सामानो को चेक करने पर पता चला कि अलमीरा मे रखे बच्चो के दो नग सोने का चैन नहीं था, जिसका वजन लगभग 10 ग्राम मूल्य करीब 70 हजार था और पेंट के जेब से नगद 2 हजार 200 रुपये नहीं थे। अज्ञात चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर लगभग 72 हजार की चोरी को अंजाम दिया है।

आजाद हिन्द एक्सप्रेस सहित तीन यात्री ट्रेन में एलएचबी कोच की सुविधा

रेल यात्रियों को मिलेगी बेहतर आरामदायक एवं संरक्षित यात्रा सुविधा

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इस तारतम्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने/गुजरने वाली सभी गाडियों में योजनाबद्ध तरीके से पुराने पारंपरिक कोचों के बदले सुविधाजनक, आरामदायक और ज्यादा सुरक्षित नई तकनीक वाले एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक व सुविधायुक्त होता है। रेल परिचालन की दृष्टि से एलएचबी कोच काफी सुरक्षित भी है। वर्तमान समय की मांग पर अगर स्पीड की बात की जाए तो ये कोच सामान्य कोचों की अधिकतम गति 110-130 किमी की तुलना में 160 से भी अधिक की गति के लिए डिजाईन की गई है 7 इन कोचों में सामान्य कोचों की तुलना में ज्यादा जगह होती है। आईसीएफ़ कोच की तुलना में एलएचबी कोच में बर्थ की संख्या भी अधिक होती है 7 इससे रेल यात्रियों को

अधिक से अधिक बर्थ की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता मिल रही है। एलएचबी कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। वही दाएं बाएं मूवमेंट के लिए भी सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है।

उपयुक्त सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये गाड़ी संख्या 12129/12130 पुणे-हावड़ा-पुणे आजाद हिन्द एक्सप्रेस, 11756/11755 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी)-रीवा एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 12767/12766 हजूर साहिब नान्देड-सांतरागाछी-हजूर साहिब नान्देड एक्सप्रेस में पारंपरिक कोचों के बदले एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस में 15 फरवरी, 2025 से तथा 12130 हावड़ा-पुणे आजाद हिन्द एक्सप्रेस में 17 फरवरी, 2025 से उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार 11756 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी) एक्सप्रेस में 19 फरवरी, 2025 से तथा 11755 नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी)-रीवा एक्सप्रेस में 20 फरवरी, 2025 से उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा 12767 हजूर साहिब नान्देड-सांतरागाछी एक्सप्रेस में 10 फरवरी, 2025 से तथा 12766 सांतरागाछी- हजूर साहिब नान्देड एक्सप्रेस में 12 फरवरी, 2025 से उपलब्ध रहेगी। इससे यात्रियों को बेहतर आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी।

बलौदाबाजार केस: निरीक्षक अमित तिवारी हो सकतें हैं गिरफ्तार

■ **अग्रिम जमानत याचिका खारिज**

बलौदा बाजार। बलौदा बाजार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में छह महीने पहले हुए बहु चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर के अधिकारी की संलिप्तता सामने आई है। बलौदा बाजार सिटी कोतवाली में तात्कालिक पदस्थ थाना प्रभारी अमित तिवारी के खिलाफ बलौदा बाजार के सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ एवं जांच के बाद निरीक्षक अमित तिवारी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग एवं अवैध पैसे वसूली के मामले में अपराध क्रमांक 260/2024 में जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है।

अमित तिवारी के ऊपर 15 लाख के लेन-देन में हिस्सेदारी का बड़ा आरोप लगा है। मामला बलौदा बाजार से बहुचर्चित हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। जांच में अब इसके तार पुलिस अधिकारी से भी जुड़ चुके हैं। अपराध दर्ज होने के बाद निरीक्षक अमित तिवारी ने बलौदा बाजार सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।

न्यायाधीश का कहना है कि मामला संजीदा है और पैसे लेने की हिस्सेदारी में अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल है, इसलिए यह जमानत याचिका खारिज की जाती है।

अब इस मामले में कभी भी निरीक्षक अमित तिवारी की गिरफ्तारी बलौदा बाजार पुलिस कर सकती है। बता दें कि पूर्व में भी इस मामले में आठ से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें महिला दलाल राजनेता वकील, पुलिस आरक्षक, एवं पत्रकार शामिल हैं। इनमें से अधिकतर जमानत से बाहर आ चुके हैं। वहीं, कुछ अभी भी जेल में बंद है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने नायब सैनी को विधायक दल के नेता चुने जाने पर दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर लिखा कि आपके नेतृत्व में निश्चित ही हरियाणा राज्य प्रगति के आदर्श प्रतिमान स्थापित करेगा। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित हुए। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। लेकिन भाजपा ने तीसरी बार राज्य में जीत हासिल की। भाजपा ने 90 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। अन्य दलों में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटें जीतीं और 3 सीटों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल किया।

प्रधानमंत्री मोदी 20 को अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर उस दिन अंबिकापुर में मौजूद रहने का आग्रह किया है। नायडू ने अपने पत्र में कहा है कि एएआई ने 225 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ रीवा, सरसावा और अंबिकापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का विकास पूरा कर लिया है। ये अवसंरचनात्मक प्रगति क्षेत्रीय हवाई संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, साथ ही स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगी, जिससे संबंधित क्षेत्रों और पूरे राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। नव विकसित टर्मिनल भवनों को सालाना 10 लाख यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो यात्री हैंडलिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ दौरे पर बिहार के वन मंत्री प्रेम कुमार ने सीएम साय से की मुलाकात

रायपुर। बिहार के वन मंत्री प्रेम कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने आज नया रायपुर स्थित सीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। बता दें, डॉ. प्रेम कुमार छत्तीसगढ़ में बुधवार से आयोजित 27 वें अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज खरीदी व्यवस्था और धान उपार्जन व्यवस्था का भी जायजा लेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे यह मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 3.9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और यह बढ़ोतरी इस साल एक अक्टूबर से प्रभावी होगी। सीएम साय ने कहा कि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, इसलिए सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे यह केंद्र सरकार के बराबर हो जाएगा। इस साल मार्च की शुरुआत में साय सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह मूल वेतन का 46 प्रतिशत हो गया था।

शिक्षक भर्ती की मांग पर डटा बीएड-डीएड संघ, 18 तक का दिया सरकार को समय

रायपुर। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड-बीएड संघ का नया रायपुर तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बीते 30 दिनों में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं के बाद अब संघ 18 अक्टूबर तक मांग पूरी होने पर 19 अक्टूबर को नेशनल हाइवे पर चक्काजाम की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड-बीएड संघ के अध्यक्ष दाउद ख़ान ने मीडिया से चर्चा में बताया कि शिक्षक भर्ती नहीं होने से डिप्रेशन में बिलासपुर में एक युवा ने आत्महत्या कर ली है। सरकार को एक साथ कितनी जान चाहिए बता दें। उन्होंने कहा कि एक तरफ 75,000 शिक्षकों का पद ख़ाली हैं, जिसकी वजह से अभिभावक-बच्चे स्कूलों में ताला लगा रहे हैं। दूसरी तरफ़ डिग्रीधारी बेरोजगार सरकार ने अपने वादे के अनुरूप नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं।

अपने ही रायफल से फायर होने से जवान हुआ घायल, रायपुर रेफर

बीजापुर। सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के जवान नक्सल प्रभावित इलाके सिलगेर से अभियान पर रवाना हुए थे, इसी दौरान अपने ही रायफल से फायर होने से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। घायल जवान का नाम मुकेश उरांव है और वह सिलगेर में 150वीं बटालियन में पदस्थ था। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जवान रोजाना की तरह आज भी मोटर साइकिल पर सवार होकर ड्यूटी पर निकले थे, इसी दौरान रायफल का स्टीकर दबाने से जवान के पेट पर गोली लगी है।

रायपुर दक्षिण उप चुनावः विधानसभा क्षेत्र में ही लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता

चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तैनात होंगी पांच कंपनियां, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मिलेगी खास सुविधा

रायपुर। रायपुर दक्षिण उप चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने उप चुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी। नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी। मतदान के दौरान पांच कंपनियां तैनात रहेगी।

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उप चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान सुरक्षा बलों की 5 कंपनियां भी तैनात की जाएगी। अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर होगी। नाम वापसी 30 अक्टूबर को रहेगी। मतदान 13 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर 2024 होगी।

इस बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान सुरक्षा बलों की 5 कंपनियां तैनात की जाएगी। मतदाता पहचान पत्र के आधार पर ही मतदान होगा।

इसके साथ ही 12 अन्य पहचान पत्र भी मान्य किए गए हैं। चुनाव की घोषणा होते ही रायपुर दक्षिण विधानसभा में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 253 मतदान केंद्र होंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 7 हजार 936 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1 लाख 33 हजार 713 और महिला मतदाता की संख्या 1 लाख 37 हजार 171 है। यानी कि इस सीट पर महिला मतदाता की संख्या पुरुष मतदाता से अधिक है। थर्ड जेंडर के कुल मतदाताओं की संख्या 52 है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5014 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1711 है। 100 साल की आयु पूरे करने वाले मतदाताओं की संख्या 56 है। 85 आयु वर्ग के मतदाता अगर घर पर मतदान करना चाहते हैं, यानी कि डाक मत पत्र से तो 18 अक्टूबर से 5 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं या फिर मतदान केंद्र में मतदान कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग रथ भी निशुल्क रहेगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 253 मतदान केंद्र हैं, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय भी इतनी ही संख्या थी।

रायपुर दक्षिण उपचुनाव कार्यक्रम

अधिसूचना प्रकाशन- 18 अक्टूबर
नामांकन दाखिल- 25 अक्टूबर से शुरुआत
मतदान की तारीख- 13 नवंबर
मतगणना की तारीख- 23 नवंबर
कुल मतदान केंद्र- 253
कुल मतदाताओं की संख्या- 2 लाख 7 हजार 936
पुरुष मतदाताओं की संख्या- 1 लाख 33 हजार 713
महिला मतदाताओं की संख्या-1 लाख 37 हजार 171
थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या- 52

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र भी बनाया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10 संगवारी मतदान केंद्र होंगे, जो महिला मतदाता दल की ओर से संचालित होंगे। इसी तरह 5 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। 1 दिव्यांग मतदान केंद्र संचालित होगा। 5 मतदान केंद्र युवाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। मतदान केंद्रो में बुजुर्ग लोगों के लिए और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र भी सहयोग करने के लिए रखे जाएंगे।

ये दस्तावेज होंगे मान्य- मतदान केन्द्रों में मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही श्रम मंत्रालय की ओर से स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एंप्लॉई को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सर्विस आइडेंटी कार्ड मान्य होगा। विधायक और सांसदों को जारी किया गया ऑफिसियल आइडेंटी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कार्ड मान्य रहेगा।

भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर साधा निशाना

■ ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर करारा निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र जनता महायुति सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि शिवाजी की मूर्ति तक गिर गई। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। साथ ही पूर्व सीएम ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया।

बता दें कि विगत मंगलवार (15 अक्टूबर) को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित की थी। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। राज्य में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता है। वहीं क्राइम का बोलबाला है। यहां बीच सड़क पर नेता को मार दिया जाता है।

बघेल ने भारतीय चुनाव आयोग को भी घेरा है। उन्होंने ईवीएम की बैटरी पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि पाकिस्तान में पहले अंपायर भी उनकी टीम की तरफ से खेलते थे। वैसे ही भारत की चुनाव एजेंसियां बीजेपी की तरफ से खेलती हैं। चुनाव आयोग ने जो बैटरी इजाद की है वो 60 फीसदी इस्तेमाल करने के बाद अपने आप 99 फीसदी हो जाती है। उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए।

हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इसे देखते हुए पार्टी की तरफ से 11 बड़े नेताओं को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया है। इन नेताओं में भूपेश बघेल के अलावा, टीएस सिंहदेव, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सहित अन्य नेताओं का नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा विदर्भ के लिए तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

भाजपा नेता के वायरल वीडियो पर सीएम का बयान, कहा-

हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की चल रही साजिशः साय

रायपुर। कांकेर में भानुप्रतापपुर से भाजयुमो मंडल अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नोटों की गड्डियों के साथ कार से सफर करते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अब इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नोटों के बंडल वाले वीडियो का वेरीफाई कर रहे हैं। आजकल फेक वीडियो भी बहुत चल रहा है। हमारे लोग और सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है।

बता दें कि मंगलवार को भानुप्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी का नोटों के गड्डियों के साथ कार में सफर करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आकाश सोलंकी भाजयुमो जिलाध्यक्ष राजा पांडे का करीबी माना जाता है। नोटों के गड्डियों के साथ वीडियो पर पूर्व सीएम ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि क्या बात है! विष्णुदेव साय जी आपका सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है! पहचाना इन्हें जो नोट की गड्डियों के साथ मूछों में ताव दे रहे हैं? लीजिए, आसान कर देता हूं, ये भानुप्रतापपुर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी हैं। सुना है बेरोजगार हैं। सामान्य परिवार से आते हैं। अब ये बताइए कि 'सुशासन' में इसकी जांच होगी या वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा, भानुप्रतापपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी, जो कि कुछ ही महीने पहले बेरोजगार था, वह 70 से 80 लाख रुपये नकद का खुलेआम दिखावा कर रहा है। छोटे से भाजपा कार्यकर्ता के इस दौलत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बड़े नेता क्या गुल खिला रहे होंगे। क्या भाजपा सरकार की पुलिस, ईडी, आईटी कोई कार्रवाई करेगी या फिर सिर्फ निर्दोष कांग्रेसियों को सताया जाएगा?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा, भिलाई में तैयारियां हुईं शुरु

भिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को अपने दो दिवसीय संभावित दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही है। वे 26 अक्टूबर को भिलाई में रहेंगी।इस दौरान आईआईटी भिलाई के कैम्पस में पहली बार दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगी। भिलाई में यह पहला दीक्षांत समारोह है। हालांकि आईआईटी खुलने के बाद तीसरे और चौथे सत्र का एक साथ दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है।वहीं भिलाई बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति भिलाई आगमन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।

दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने इस बारे में जानकारी दी।एएसपी ने कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शरू कर दी गई हैं। राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार ने पिछले दिनों इसे लेकर बैठक कर निर्देश भी जारी किए थे। इसके बाद दुर्ग जिले में स्थल निरीक्षण से लेकर आयोजन को लेकर अन्य तैयारियां की जा रही हैं।

एएसपी अभिषेक झा ने कहा राष्ट्रपति 25 और 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगी। वे दुर्ग के अलावा रायपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति एम्स रायपुर, एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी।

भिलाई में राष्ट्रपति आगमन को लेकर बीजेपी के भिलाई कार्यालय में कार्यकर्ता और नेताओं ने बैठक हुई।वहीं बैठक में पहुंचे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भिलाई और प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होने वाला है। आने को लेकर तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आना आदिवासी समाज के लिए हर्ष का विषय है।

गढ़फुलझर को सीएम साय ने दी सौगात, रनेश्वर रामचंडी मां की पूजा में हुए शामिल

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रामचंडी मंदिर

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बसना विकासखंड के गढ़फुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज के स्नेह सम्मेलन और बंधु मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम साय के साथ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्थानीय जिले के चारों विधायक भी मौजूद थे।

सीएम साय ने की रनेश्वर रामचंडी मां की पूजा = मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले रामचंडी मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। फिर विशाल सामाजिक सभा में शामिल हुए। जहां उन्होंने अपने भाषण मे कोलता समाज को बधाई देते हुए कहा कि कोलता समाज भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को साथ लेकर चलने वाला समाज है।क्योंकि इस समाज के अधिकांश लोग खेती-किसानी करने वाले लोग हैं।ओडिशा की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से इस राज्य से जुड़ा है।दोनों प्रदेश के लोगों का रोटी-बेटी का संबंध है।दोनों के अचार-विचार मिलते हैं।

प्रभु श्रीराम ने मां चंडी को किया था प्रसन्न = आपको बता दें कि मान्यता है कि प्रभु श्रीराम ने रावण से रण में विजय पाने के लिए देवी की 9 दिन तक देवी की उपासना की थी।राम साधक के रूप में कठोर साधना कर चंडी को प्रसन्न किए थे। इसके बाद मां चंडी से विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी समय से देवी के उस स्वरुप का नाम रनेश्वर रामचंडी पड़ा।माता रनेश्वर रामचंडी बाबा बिशा सहे कोलता समाज की कुल देवी के रूप में फुलझर के गढ़ में प्रतिष्ठित हैं।जहां एक ओर राजा तालाब और दूसरी ओर रानी तालाब है। यहां आदिवासी भैना राजा का राज्य था। जिन्होंने गुरु नानक देव जी को 4 एकड़ भूमि देकर गांव का नाम नानक सागर कर सम्मानित किया।साल 2004 में रनेश्वर रामचंडी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष रामचंडी दिवस का आयोजन धूमधाम से होता है।

मुख्यमंत्री ने सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।इसके बाद शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाया।इसके बाद समाज के लिए कई घोषणाएं भी की।जिसमें गढ़फुलझर में सर्व समाज मंगल भवन के लिए 50 लाख रूपए ,रामचंडी गढ़फुलझर क्षेत्र को पर्यटन के रूप मे विकसित करने और ओडिशा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क को भी बेहतर बनाने का ऐलान किया है।

छत्तीसगढ़ में 306 गांव में कोलता समाज निवासरत है। जिसे 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। जिसके अंतर्गत 30 शाखा सभा आते हैं, प्रत्येक 100, व्यक्ति में एक ग्राम प्रतिनिधि होता है। कोलता समाज प्रमुख रूप से कृषि कार्य करते हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और परंपरा तथा जड़ से जुड़े रहने वाले होते हैं।शिक्षा के प्रति विशेष आग्रह रखने वाले, धार्मिक और सेवाभावी होते हैं। इस दिन रामचंडी दिवस में छत्तीसगढ़ के 8 और ओडिशा के 12 जिले के लोग उपस्थित होते हैं। इस कार्यक्रम में कोलता समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी उपस्थित होते हैं।

डीईओ से मिलकर शिक्षक मोर्चा पदाधिकारियो ने शीघ्र प्रधानपाठक पर पदोन्नति की मांग की

डीईओ ने दीपावली पूर्व पदोन्नति करने की बात कही

रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधानपाठक पदोन्नति करने हेतु जिला संचालक द्वय ओमप्रकाश सोनकला एवं भानुप्रताप डहरिया के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर डॉ.विजय कुमार खंडेलवाल से मिलकर प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के पद पर शीघ्र पदोन्नति करने के लिए ज्ञापन सौपा गया। जिस पर डीईओ द्वारा 15/10/2024 को अंतिम दावा आपत्ति पश्चात दीपावली पूर्व पदोन्नति के लिए काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना करने का आश्वस्त किया गया।

अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 3 इंद्रकुमार देवांगन को विगत 10 माह का लंबित वेतन भुगतान हेतु बात रखी गई जिस पर डीईओ द्वारा आवेदन लेकर उच्च कार्यालय को अवगत कराकर अतिशीघ्र वेतन दीपावली पूर्व भुगतान कराने की बात कही।डीईओ से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा से ओमप्रकाश सोनकला, भानुप्रताप डहरिया, आयुष पिल्ले,जीतेन्द्र मिश्रा, अब्दुल आसिफ खान, कन्हैया कंसारी, अतुल शर्मा, गोपाल वर्मा, बुद्धेश्वर बघेल, रविंद्र सॉन्ग सुरतान, मनोज मुछावड, मदन वर्मा, कृष्ण कुमार जांगड़े, प्रफुल्ल मांझी, संतोष सोनवानी, जितेंद्र निषाद, इंद्रकुमार देवांगन, वर्षा दुबे सहित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

कार्यालय, कलेक्टर (जिला निर्माण समिति), जिला उत्तर बस्तर - कांकेर

-:: अल्प कालिन निविदा ::-

एन.आई.टी. क्रमांक / 46 से 49/ जि.नि.स./2024-25 कांकेर, दिनांक 11.10.2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों के लिए निम्नानुसार मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - 23/10/2024 (सायं 5:00 बजे तक) (रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से)
2. आवेदन परीक्षण पश्चात् मनी रसीद कटाने की अंतिम तिथि- 25/10/2024 (सायं 05:00 बजे तक)
3. निविदा प्रपत्र वितरण की तिथि- 28/10/2024 (प्रात: 11:00 बजे से)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि- 17/11/2024 (सायं 05:00 बजे तक)
5. निविदा खोले जाने की तिथि- 19/11/2024 (दोपहर 12:30 बजे से)

इस कार्य की विस्तृत निविदा कार्यालयीन अवधि अंतर्गत कार्यालय में देख सकते हैं।

क्र.	NIT No.	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	धरोहर राशि	टीप
1	46	नवीन तहसील कार्यालय भवन बान्दे, वि.ख. कोयलीवेड़ा	71.12	53,500	
2	47	नवीन तहसील कार्यालय भवन आमावेड़ा, वि.ख. अंतागढ़	71.12	53,500	
3	48	नवीन तहसील कार्यालय भवन कोयलीवेड़ा, वि.ख-कोयलीवेड़ा	71.12	53.500	
4	49	अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण अंतागढ़, विकासखण्ड-अंतागढ़	127.62	96,000	

कलेक्टर,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

जी-242503201/8

क्या एक नई शुरुआत कर पाएगी जम्मू-कश्मीर की नई सरकार

योगेन्द्र यादव

क्या उमर अब्दुल्ला की नई सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल पाएगी, जिसका इस प्रदेश को बहुत लंबे वक्त से इंतजार है? 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव और इस चुनाव के बीच प्रदेश का संवैधानिक और राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। जम्मू-कश्मीर अब एक विशेष राज्य की बजाय एक सामान्य राज्य भी नहीं बचा। विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका है, अब जम्मू-कश्मीर बस एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में लैफ्टिनैंट गवर्नर को विशेष अधिकार हासिल है। नए परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी का आंतरिक राजनीतिक संतुलन बदल चुका है। अब जम्मू का वजन कश्मीर के बराबर हो गया है। जम्मू-कश्मीर की परछाईं में गुमनाम और नजरअंदाज रहा लद्दाख अब एक अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश बन चुका है, अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। उधर पाकिस्तान अपनी परेशानियों में उलझा है। कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान का साथ देने वाली ताकतें चीन की चिंता में पड़ी हैं। इस लिहाज से यह पिछले 6 साल से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने का एक बड़ा अवसर है। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए, उसमें कश्मीर घाटी समेत सभी इलाकों की जनता की अच्छी भागीदारी हुई और 6 साल के बाद प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई। इस चुनाव में जनता ने केन्द्र की सत्तारूढ़ भाजपा और राज्य में नई सरकार संभालने वाली नैशनल कांफ्रैंस गठबंधन दोनों को सबक सिखाए हैं। इस चुनाव में भाजपा की रणनीति यह थी कि जम्मू इलाके में वह एक तरफा जीत हासिल कर ले, जहां सीटों की संख्या बढ़ गई है। उधर कश्मीर घाटी में वोटों और सीटों का बंटवारा हो जाए और काफी सीटें उन दलों को मिल जाएं, जो खुले या छुपे तौर पर भाजपा का साथ दे सकती हैं। ऐसे में भाजपा पहली बार अपने नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में सरकार बना पाएगी। जरूरत पड़े तो राज्यपाल द्वारा नामांकित 5 विधायकों की मदद ली जाएगी। यह योजना सफल नहीं हुई। जम्मू के हिन्दू इलाके में तो भाजपा को एकतरफा सफलता मिली, लेकिन जम्मू के पहाड़ी और कबायली इलाके में वैसी कामयाबी नहीं मिली। उधर कश्मीर घाटी तमाम गाजे-बाजे के बावजूद भाजपा को अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले, जहां उम्मीदवार मिले, उन्हें वोट नहीं मिले। महबूबा मुफ्ती, राशिद इंजीनियर और सज्जाद लोन सरीखे जिस-जिस पर भाजपा की बी टीम होने की तोहमत लगी, उन संभावित सहयोगियों को कश्मीर घाटी की जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया। सबक ये हैं कि सुरक्षा बलों के सहारे जनता को डराया जा सकता है लेकिन उनका दिल नहीं जीता जा सकता। प्रचारतंत्र के सहारे बाकी देशों को मोहक तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं लेकिन स्थानीय जनता को भरमाया नहीं जा सकता। साथ ही चुनाव जीतने वाली नैशनल कांफ्रैंस गठबंधन के लिए भी जनता के सबक हैं। बेशक कश्मीर घाटी ने पूरी तरह से नैकां को अपना समर्थन दिया है लेकिन चार महीने पहले इसी कश्मीर घाटी में बारामूला संसदीय क्षेत्र की जनता ने खुद उमर अब्दुल्ला को चुनाव में पटखनी दी थी और उनके मुकाबले जेल में बंद राशिद इंजीनियर को पसंद किया था। इन चार महीनों में कश्मीर घाटी की जनता का मन नहीं बदला, बस उनकी उम्मीद का बोझ एक बार फिर नैशनल कांफ्रैंस के कंधे पर आ गया है। यह बोझ बहुत भारी है। सी.एस.डी.एस.-लोकनीति का सर्वेक्षण दिखाता है कि जनता की असल चिंता बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों की है। इन उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं होगा। यह चुनौती और भी बढ़ जाती है क्योंकि जम्मू क्षेत्र के हिंदू मतदाताओं में नैशनल कांफ्रैंस और कांग्रेस का गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस बिल्कुल असफल हो गई। नई सरकार के सामने यह चुनौती रहेगी कि वह अल्पसंख्यक हिन्दुओं का विश्वास जीते। नई सरकार की पहली चुनौती जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा हासिल करना होगी। इसे केन्द्र सरकार और संसद ही कर सकती है।

कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है आतंकवाद

योगेंद्र योगी

सुरक्षा बलों ने 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 साल बाद से किसी एक अभियान में माओवादियों आतंकियों की यह सर्वाधिक मौतों की संख्या है। इस घटना ने देश में आतंकवाद के घाव फिर से हरे कर दिए। देश में हर तरह की आतंकी वारदातें कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान शुरु हुई। कांग्रेस की गलत नीतियों से ऐसी रक्तरंजित घटनाओं का परिणाम अभी तक देश भुगत रहा है। आतंकवाद चाहे जम्मू-कश्मीर का हो, नक्सलियों का, पूर्वोत्तर में या फिर पंजाब में खालिस्तान का रहा हो, देश ने कांग्रेस की गलतियों की भारी कीमत चुकाई है। इसी तरह दशकों तक तीन राज्यों में व्याप्त रहा चंबल की बीहड़ों में डकैतों के अपराधों का काला इतिहास भी कांग्रेस के शासन के दौरान लिखा गया। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि कांग्रेस ने इन गलतियों से सबक नहीं लिया। आतंकवाद चाहे जम्मू-कश्मीर में हो या फिर नक्सलियों का हो कांग्रेस ने कभी भी केंद्र की मोदी सरकार की तरह सख्ती नहीं दिखाई। इसके विपरीत कांग्रेस का रवैया वोट बैंक की राजनीति के कारण आतंक समर्थकों के प्रति सहानुभूति का रहा है। लापरवाही और उपेक्षापूर्ण नीतियों के साथ ही राजनीतिक फायदे के लिए की गई आतंकवाद की अवहेलना की कीमत कांग्रेस ने भी चुकाई है। 25 मई 2013 को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नक्सली विद्रोहियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दरभा घाटी के झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्या चरण शुक्ला, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल की मौत हो गई।

कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में शासन के दौरान ही तीनों तरह का आतंक पनपा है। इसमें चंबल में डकैतों का काफी हद तक सफाया हो गया। जम्मू-कश्मीर में पाक परस्त और देश के कुछ राज्यों में नक्सली आतंक अब तेजी सीमिट रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार दोनों तरह के आतंकियों पर काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाब रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि 2026 नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। शाह ने कहा कि 30 साल के बाद पहली बार वामपंथी उग्रवाद से मरने वाले लोगों की संख्या 100 से कम रही है। हिंसा की घटनाओं में करीब 53 फीसद की कमी आई है। नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 96 की जगह 42 जिले तक सीमित रह गई हैं। इन 42 जिलों में से 21 जिले नए बने हैं। इनमें से करीब 16 जिले ही नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं।

देश की सुरक्षा से संबंधित कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम सिर्फ देश की आम अवाम को नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को आतंकियों से निपटने के लिए न सिर्फ करोड़ों रुपए बहाने पड़ रह हैं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मानवीय क्षति उठानी पड़ी है। नक्सल आतंकवाद का उदय पश्चिमी बंगाल से कांग्रेस शासन के दौरान ही हुआ था। यह फैलते हुए देश के करीब आठ राज्यों में तक पहुंच गया। इनमें से ज्यादातर राज्यों और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें नक्सलियों की रोकथाम करने में विफल रही। केंद्र और राज्य मिलकर काम नहीं कर सके। नक्सली देश के लिए नासूर बन गए। मौजूदा केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने खून-खराबा करने वाले नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने की ठान ली है।

नक्सली प्रभावित राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर भी आतंकवाद की आग में अभी तक सुलग रहा है। इस अशांत केंद्रशासित प्रदेश में आजादी के बाद से ही नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का शासन रहा है। केंद्र की कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की सरकार आतंकियों को सबक सिखाने में पूरी तरह नाकाम रही। पाकिस्तान की शय पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया। नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय दल आतंकियों के प्रति नरम रवैया रखते रहे। आतंकियों के समर्थन में पत्थरबाजी की घटनाओं ने सुरक्षा बलों नुकसान पहुंचाया। धारा 370 और 35 ए के कारण विशेष दर्जा प्राप्त इस प्रदेश में यह कानून आंतकियों की ढाल बनता रहा है। आतंकी वारदातों के बावजूद कांग्रेस ने कभी भी इस कानून को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत मुस्लिम वोटों के कारण कांग्रेस कभी भी भाजपा जैसी सख्ती नहीं दिखा पाई।

नौबत यह आ गई कि पाकपरस्त आतंकी संगठनों ने केंद्र में कांग्रेस के शासन के दौरान देश में बम-धमाके करके कानून-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। केंद्र की कांग्रेस सरकार की नाकामी और ढुलमुल सुरक्षा नीति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था लगभग चौपट हो गई। पाकपरस्त आतंकियों के हौसले इतने बढ़ गए कि 13 दिसंबर, 2001 को दिल्ली के संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में नौ लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में कम से कम 174 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 20 सुरक्षा बल कर्मी और 26 विदेशी नागरिक शामिल थे। डेढ़ दशक पहले तक आतंकियों ने कहर बरपा रखा था। कांग्रेस केंद्र और ज्यादतर राज्यों में सत्ता में रहने के बावजूद आतंकियों का खात्मा नहीं कर सकी।

देश में आतंक का यह हाल था कि 2006 में देश के 608 जिलों में से कम से कम 232 जिले विभिन्न तीव्रता स्तर के विभिन्न विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त थे। अगस्त 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन का कहना था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद ने जोर पकड़ लिया। केंद्र की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण लंबे अर्से तक पंजाब आतंकवाद की आग में धधकता रहा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप न सिर्फ हजारों निर्दोष लोग मारे गए बल्कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को जान से हाथ धोना पड़ा। पंजाब में दर्जनों कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी जान गंवा कर खालिस्तानी आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ी।

पंजाब की तरह पूर्वोत्तर को संभालने में केंद्र की कांग्रेस सरकार विफल रही। इन राज्यों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस नहीं कर सकी। दशकों तक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय आतंकियों की मार झेलता रहा। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड, इसाक मुइवा ने एक स्वतंत्र नगालैंड की मांग करते हुए क्षेत्र में भारतीय सेना के ठिकानों पर कई हमले किए। सरकारी अधिकारियों के अनुसार 1992 से 2000 के बीच 599 नागरिकों, 235 सुरक्षाबलों और 862 आतंकवादियों ने अपनी जान गंवाई।

आतंकियों की इन करतूतों से साबित है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हालात पर नियंत्रण नहीं पा सकी। भाजपा ने केंद्र में दस पहले सत्ता संभालते ही देश के किसी भी हिस्से में मौजूद आतंकवाद के खात्मे को प्राथमिकता पर रखा। केंद्र की आंतरिक सुरक्षा नीतियों की बदौलत पूर्वोत्तर में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लग सका। भाजपा सरकार की सख्त सुरक्षा नीतियों के कारण पाकपरस्त आतंकियों के हौसले पस्त हो गए। जम्मू-कश्मीर में कुछ आतंकी वारदातों के सिवाए देश में कहीं भी बम धमाके नहीं हुए। इसमें महत्वपूर्ण सफलता धारा 370 हटने के बाद मिली, जिससे पत्थरबाजी खत्म होने के साथ विकास की नई इबारत लिखी गई। सवाल यही है क्या कांग्रेस आतंकवाद और कानून-व्यवस्था को लेकर इतिहास से कोई सबक सीखेगी। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के साथ सत्ता में आई कांग्रेस के लिए इस प्रदेश में शांति कायम रखना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखना यह है कि कांग्रेस इस परीक्षा में सफल हो पाती है या नहीं।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

इसी प्रकार उक्त वेद के विशिष्ट मन्त्र-समुदाय को इतिहास और पुराण नाम से भी याद किया जाता था। जिन मन्त्रों में प्रायः किन्हीं कल्पित व्यक्तियों के सम्वादरूप से अथवा आख्यानरूप से कुछ रहस्य प्रकट किया गया हो उन मन्त्रों को इतिहास और जिन मन्त्रों में सृष्टि- प्रक्रिया का तात्त्विक निर्देश हो उन्हें पुराण कहनेका व्यवहार हो गयः था।

गाथा, नाराशंसी और श्लोक-संज्ञक उपभेद भी उक्त इतिहास पुराण नामक विभाग के ही अङ्ग समझे जाते थे। इस तरह ऋगादि चार भेदों के साथ इतिहास पुराण नामक भाग को सम्मिलित करने पर उस एक ही वेद में पाँच भागों का समावेश भी समझा जाता था ।

कुछ ऋषि उसी एकत्व-संख्यावच्छिन्न श्रुतिसंदर्भ में सर्प-वेद, पिशाचवेद, अग्रवेद, वाकोवाक्य, अनुशासन-विद्या, उपनिषद्, सूत्र, व्याख्यान आदि अनन्त विद्याओं का समावेश देखकर उसमें, अनन्तत्व की बुद्धि रखते थे । तात्पर्य यह है कि वह गुरुपरम्परा द्वारा श्रुत श्रुति- समुदाय मौलिकरूप में एक होता हुआ भी विभिन्न दृष्टियों से देखा जाता था। उपर्युक्त विचार के समर्थन में नीचे लिखे प्रमाण दर्श- नीय हैं।

(क) बेदेन रूपे व्यपिवत्। (शुक्ल यजुः 16।78) (ख) ते सर्वे त्रयो वेदाः। (ग) चत्वारो वा इमे वेदाः। (गोपथ पूर्व0 2।16) (शतपथ 10।4।2।25) (घ) इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्। (छान्दोग्य 7।2।1) (ङ) अनन्ता वै वेदाः । (तैत्तिरीय 3।10।11।3)

अर्थात् - एक दो तीन चार पांच और अनन्त वेद हैं। यह इन प्रमाणों में यथामक्र अङ्कित है। कहना न होगा कि यह संख्या-वैचित्र्य पूर्वोक्त भावनाओं के ऊपर ही अवलम्बित है। यहां तक हमने वेदों की परम्परा का निरूपण किया है। अब पुराणों के मौलिक तत्त्व और उसके परम्पराजन्य विकाश का रहस्य प्रकट किया जाता है।

क्रमशः ...

महर्षि वाल्मीकि जयंती

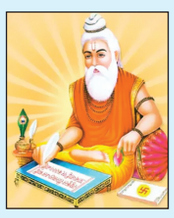

वाल्मीकि जयंती महान लेखक और ऋषि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता होने के साथ-साथ संस्कृत साहित्य के पहले कवि भी हैं। रामायण, जो भगवान राम की कहानी कहती है, संस्कृत में लिखी गई थी और इसमें 24,000 छंद हैं जो सात 'कांडों' (कैंटोस) में विभाजित हैं। इस पूज्य संत के सम्मान में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस दिन को 'प्रगट दिवस' के रूप में भी जाना जाता है और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में उत्साह के साथ मनाया जाता है।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, यानी अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर-अक्टूबर से मेल खाती है। वाल्मीकि जयंती बृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी।

वाल्मीकि जयंती का हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है क्योंकि यह महर्षि वाल्मीकि के अद्वितीय योगदान को याद करता है। उन्होंने रामायण, महाभारत और कई पुराणों सहित कुछ अद्भुत रचनाएँ लिखीं। वाल्मीकि जयंती का उत्सव एक महान संत को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी सीमाओं पर काबू पाया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जनता को सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भगवान राम के मूल्यों को बढ़ावा दिया और उन्हें तपस्या और परोपकार के व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि अपने वनवास के दौरान भगवान राम से मिले थे। भगवान राम द्वारा सीता को अयोध्या का राज्य छोड़ने के लिए कहने के बाद, उन्होंने उन्हें बचाया और उन्हें आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अपने आश्रम में जुड़वां बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। महान ऋषि उनके शिक्षक बन गए जब वे छोटे थे, उन्हें रामायण पढ़ा रहे थे, जिसमें 24,000 छंद (श्लोक) और सात सर्ग (कांड) थे।

एक अन्य लोकप्रिय मान्यता यह है कि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक वर्षों में रत्नाकर नामक एक राजमार्ग डाकू थे। उनका जन्म प्राचीन भारत में गंगा के तट पर प्रचेतस नाम के एक ऋषि के यहाँ हुआ था। रत्नाकर उनका जन्म नाम था। एक बच्चे के रूप में, वह जंगलों में खो गया और एक शिकारी द्वारा पाया गया, जिसने उसे अपने बेटे के रूप में पाला। वह अपने पालक पिता की तरह एक शिकारी के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन उसने एक डाकू बनकर अपनी आजीविका का भी पूरक बनाया। वह अंततः महर्षि नारद से मिले और उन्हें लूटने का प्रयास किया। वह नारद मुनि से मिलने तक लोगों को लूटता और हत्या करता था, जिसने उसे भगवान राम का भक्त बना दिया। वर्षों के ध्यान के बाद, एक दिव्य आवाज ने उनकी तपस्या को सफल घोषित किया और वाल्मीकि नाम दिया, जो चींटी-पहाड़ियों से पैदा हुए थे। संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि होने के कारण बाद में उन्हें आदि कवि के नाम से जाना गया। तब से, हिंदू भक्त उनके कार्यों, विशेष रूप से महान महाकाव्य- रामायण का पाठ करना जारी रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि की जन्म तिथि और जन्म समय अज्ञात है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार, वे लगभग 500 ईसा पूर्व रहते थे।

बढ़ते तनाव के लिए कनाडा जिम्मेदार

अनिल त्रिगुणायत

अगर हमारी अखंडता और संप्रभुता पर कोई खतरा होगा, तो हमें उसे रोकने के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। अब इससे अधिक भारत कनाडा से क्या कह सकता है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी घटना में भारत शामिल है, तो उन्हें इस बारे में ठोस सबूत सामने रखना चाहिए। इसके बजाय कनाडा की ओर से सार्वजनिक रूप से आरोप लगाये गये और भारतीय उच्चायोग को मामले में डालने की कोशिश हुई। इससे तो यही संकेत मिलता है कि कनाडा भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहता है।

भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव गंभीर हो गया है, पर यह स्थिति अचानक से नहीं बिगड़ी है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हमेशा से वहां सक्रिय सिख अलगाववादियों एवं आतंकवादियों को संरक्षण देते रहे हैं। जब उनके पिता पियरे ट्रूडो सत्तर और अस्सी के दशक में कनाडा के प्रधानमंत्री थे, तब उनकी भी नीतियां इसी प्रकार की थीं। यह अनायास नहीं है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों की बड़ी शरणस्थली बना हुआ है। ये तत्व वहां राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और उनका लाभ ट्रूडो उठाते रहे हैं। पिछले साल जून में एक कुख्यात खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गयी थी। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, पर कनाडा सरकार और प्रधानमंत्री ट्रूरूडो इसके लिए लगातार भारतीय कूटनीतिज्ञों, सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। इस आरोप के समर्थन में कनाडा की ओर कोई ठोस सबूत या सूचना भी भारत के साथ साझा नहीं किया गया है। सबूत देने के बजाय पिछले दिनों कनाडा ने वहां भारतीय उच्चायोग में कार्यरत कूटनीतिज्ञों को 'पर्सस ऑफ इंटरेस्ट' घोषित कर दिया, जिसकी पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है। इसका मतलब यह है कि उन अधिकारियों को निज्जर की हत्या का दोषी बनाया जा सकता है। जो स्थापित अंतरराष्ट्रीय नियम हैं, उनके अनुसार कनाडा उन अधिकारियों को अवांछित घोषित कर सकता था और उन्हें भारत वापस भेज सकता था। पर उन्हें 'पर्सस ऑफ इंटरेस्ट' घोषित करना अनुचित था।

जैसे गंभीर आरोप कनाडा ने भारतीय अधिकारियों पर लगाये हैं, उससे उनके और उनके परिजनों के जीवन पर खतरा बढ़ गया है। कनाडा सरकार के रवैये से अलगावादियों और अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही है। भारत लगातार कहता रहा है कि कनाडा के पास अगर कुछ सबूत हैं, तो वह साझा करे और फिर उस पर बातचीत होगी। अमेरिका के साथ यही हुआ। अमेरिका ने जब सूचनाओं को साझा किया, तो उस मसले पर चर्चा के लिए भारत ने एक कमिटी का गठन किया, जो इस समय अमेरिकी दौरे पर है। कनाडा के नकारात्मक रवैये को देखते हुए भारत ने वहां के उच्चायोग में अपने कर्मियों की संख्या कम कर दी थी तथा कनाडा के जो अधिकारी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कटौती की गयी थी। कनाडा ने तनाव बढ़ाते हुए भारतीय उच्चायुक्त समेत छह कूटनीतिज्ञों को बहिष्कृत किया है, तो इसकी प्रतिक्रिया में भारत को भी उसी तरह का कदम उठाना पड़ा है। फिलहाल उच्चायोग का काम कनिष्ठ अधिकारियों के जिम्मे है। तो, अभी दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध निश्चित रूप से सामान्य नहीं हैं। अब हमें देखना होगा कि वहां जो हमारे छात्र हैं और जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्हें दूतावास संबंधी सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहें। मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान स्थिति का कोई विशेष प्रभाव व्यापार एवं वाणिज्य पर होगा। आगे कनाडा अगर कुछ और कदम उठाता है, तो भारत को भी उसका जवाब देना होगा क्योंकि कूटनीति संतुलन के साथ चलती है और वह सामने वाले के व्यवहार पर आधारित होती है।

जैसा पहले कहा गया है कि अमेरिका ने वहां के एक मामले को लेकर भारत के साथ सूचनाओं को साझा किया था और उस पर भारत ने कमिटी गठित की है। पर कनाडा लंबे समय से तरह-तरह के आरोप ही लगाता रहा है। ऐसे मामलों के लिए कुछ स्थापित प्रक्रियाएं हैं। दो देश खुफिया चैनलों से, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के जरिये, कूटनीतिक माध्यमों से सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। उसके आधार पर दोनों पक्ष उस पर बातचीत करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। यह किसी मसले के हल का परिपक्व रास्ता है। दुर्भाग्य से कनाडा के मामले में ऐसा होते हुए हमने नहीं देखा। यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि कनाडा, अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने बिना किसी आधार और सबूत के अनेक देशों को तबाह किया है। उदाहरण के रूप में हम अफगानिस्तान, इराक, लीबिया आदि देशों को देख सकते हैं। कोई अतिवादी या अलगाववादी समूह इनको समर्थन करता है, तो उसकी गलतियों को ये लोग नहीं देखते। आज पश्चिम के अनेक देशों में भारत विरोधी समूह और लोग सक्रिय हैं तथा वे देश उन्हें रोकने के बजाय प्रोत्साहित ही करते हैं। हमारे लिए तो सबसे प्राथमिक विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हमारी अखंडता और संप्रभुता पर कोई खतरा होगा, तो हमें उसे रोकने के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। अब इससे अधिक भारत कनाडा से क्या कह सकता है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी घटना में भारत शामिल है, तो उन्हें इस बारे में ठोस सबूत सामने रखना चाहिए। इसके बजाय कनाडा की ओर से सार्वजनिक रूप से आरोप लगाये गये और भारतीय उच्चायोग को मामले में डालने की कोशिश हुई। इससे तो यही संकेत मिलता है कि कनाडा भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, इसका एक आयाम वहां की घरेलू राजनीति से भी जुड़ता है। हालिया सर्वेक्षण में बताया गया है कि ट्रूडो की लोकप्रियता बहुत कम हो गयी है और अगला चुनाव उनके लिए मुश्किल हो सकता है। कुछ समय पहले गुरमीत सिंह की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि उन्होंने सरकार को नहीं गिरने दिया। जाहिर है कि इसके बदले में कोई सौदेबाजी हुई होगी। खालिस्तान समर्थक लॉबी को तुष्ट करने के लिए ट्रूडो भारत के साथ तनाव बढ़ा रहे हैं ताकि उनका वोट उनको मिल जाए। ट्रूडो ने भारत पर कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी बेबुनियाद आरोप लगाया है। इसमें एक हास्यास्पद बात यह भी है कि भारत के साथ-साथ उन्होंने चीन और रूस का भी नाम लिया है। भारत और चीन का नाम एक साथ लेना अजीब बात है क्योंकि चीन के साथ उनके दूसरे तरह के रिश्ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रूडो अपरिपक्व राजनीति और कूटनीति कर रहे हैं। कनाडा या अन्य पश्चिमी देश, जो भारत विरोधी तत्वों को समर्थन और संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यदि भारत के साथ उनकी रणनीतिक सहभागिता है, तो उन्हें भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को भी प्राथमिकता देना होगा। तभी वे भारत के मित्र राष्ट्र कहे जा सकते हैं। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी धरती से भारत के विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं हो।

आज का इतिहास

1941 द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी की पनडुब्बी ने एक अमेरिकी पोत पर हमला किया।
1943 कैदियों द्वारा एक सफल विद्रोह के तीन दिनों के बाद होलोकॉस्ट, पूर्वी पोलैंड में सोबिबोर भगाने के शिविर को बंद कर दिया गया था।
1944 एथेंस में प्रतिद्वंदी पक्षियों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर किया।
1947 बर्मा और ब्रिटेन ने आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अगर बर्मा को ब्रिटेन के बाहर पूर्ण स्वतंत्रता देता है, तो वह चुनता है, इस प्रकार देश पर ब्रिटिश शासन के 300 वर्षों को समाप्त करता है।
1956 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने आज, सेला मैदान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। हालांकि, पावर स्टेशन 27 अगस्त 191956 से नेशनल ग्रिड पर कार्य कर रहा था और बिजली प्रदान कर रहा था।
1960 इक्काडोर के क्विटो शहर के पास एक बस दुर्घटना में 34 लोग मारे गए।
1962 कनाडा के एडमोंटन शहर ने नगरपालिका चुनाव आयोजित किया।
1964 ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री रॉबर्ट मेन्ज़ीस ने राजधानी कैनबरा के बीच में बर्टिल्ले लेक बर्ली ग्रिफिन खोला।
1973 तेल निर्यातक अरब देशों ने इस्राईल को तेल बेचने वाली कंपनियों और अमरीका व ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगा दिया।
1979 मदर टेरेसा को उनके काम और समर्थन के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो कलकत्ता में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया था।
1989 6.9 मेगावॉट की लोमा प्रीता भूकंप ने कैलिफोर्निया के सैनफ्रांसिस्को बे एरिया में 63 लोगों की जान ले ली, जिससे 3,757 लोग घायल हो गए।
1992 एक हैलोवीन पार्टी के लिए गलत घर में जाने के बाद, जापानीएक्सचेंज के छात्र योशीहिरो हट्टोरी को अमेरिका के लुइसियाना के गृहस्वामी बैटन रूज ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
1994 रूसी पत्रकार दिमित्री खोलोडोव की हत्या रूसी सेना के उच्च रैंक के बीच कथित भ्रष्टाचार में अपनी जांच के दौरान मोस्कोवस्कीज कोम्सोमोलेट्स के ताबूतों में की गई थी।
1998 नाइजीरिया के जेसी शहर में एक पाइप लाइन विस्फोट में 1,082 मौत हो गयी।
2003 चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की।

हिंदू हृदय सम्राट से विकास पुरुष, कैसा रहा है मोदी का राजनीतिक सफर

नीलांजन मुखोपाध्याय

जिस समय जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार था, उस समय एक और खबर चर्चा में रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस 7 अक्टूबर को सार्वजनिक पद पर रहते हुए 23 साल पूरे कर लिए। पहले गुजरात के सीएम और अब प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वह बिना थके और अधिक जोश के साथ काम करते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता।

इससे पीएम मोदी की यह इच्छा जाहिर होती है कि अगले साल जब वह 75 साल के हो जाएंगे, तब भी पद नहीं छोड़ेंगे। इस पोस्ट ने उन अटकलों को भी खारिज किया कि मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बीच तनाव की वजह से कोई और नेता उनकी जगह ले सकता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मोदी का जोरदार समर्थन किया।

अमित शाह ने मोदी की यात्रा को इस बात का प्रतीक बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन देश के हित और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर सकता है। नड्डा ने कहा कि, 'मोदी ने हमेशा सार्वजनिक सेवा और देश के निर्माण को सबसे ऊपर रखा। देश के लोगों में आत्मविश्वास जगाकर पीएम मोदी ने हमें विकसित भारत का लक्ष्य दिया है।' चूंकि मोदी का पद पर बने रहने का इरादा साफ है, इसलिए यह जरूरी है कि अक्टूबर 2001 से अब तक के समय और उनके अलग-अलग रूपों और कार्यों को समझा जाए। इस दौरान मोदी भी बदले हैं। भले ही कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन उनकी सभी उपलब्धियां नकारात्मक नहीं हैं।

गुजरात में मोदी 13 बरसों तक सीएम रहे। इस दौरान राज्य की विभिन्न इकाइयों पर बंदिशों और समाज व उसके संवाद पर अनुशासन के अलावा विकास की कहानी भी आगे बढ़ी। इसी तरह बतौर प्रधानमंत्री 10 साल में लोकतंत्र को सीमित करने के आरोप उन पर लगे। साथ ही, बढ़ती असमानता, कुछ लोगों के हाथों में सत्ता और धन के केंद्रीकरण की भी चर्चा हुई। इसके बावजूद कई अच्छे काम भी हुए हैं। वहीं, इस साल आम चुनाव में देश के कुछ हिस्सों में उनका प्रभाव भी कम

हुआ।

मोदी खुद को ऐसा नेता बताते हैं जो अनिच्छा से सत्ता में आया। उनके मुताबिक, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे अचानक कहा कि वह गांधीनगर जाकर सीएम पद संभालें। वह अनिच्छुक थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के सख्त आदेश के कारण उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ी। हालांकि, पार्टी के कुछ लोग दूसरी बात कहते हैं। उनका मानना है कि मोदी 1998 में भाजपा के महासचिव बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। जैसा कि हमेशा होता है, सच्चाई इन दोनों बातों के बीच कहीं है। मोदी कोई ऐसे शख्स नहीं थे, जिनमें सत्ता की कोई चाहत न हो। मोदी अक्सर कहते हैं कि वह सिर्फ एक 'विनम्र कार्यकर्ता' थे, जिसे पार्टी ने ऊंचा उठाया। वह अपनी साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि की भी बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि भाजपा-आरएसएस के कई नेता, जैसे उनके पहले मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल, भी सामान्य पृष्ठभूमि से ही थे।

गुजरात में मोदी का काम भाजपा की चुनावी स्थिति को सुधारना था। गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात दंगे न हुए होते तो शायद मोदी सफल न हो पाते। कच्छ में पुनर्वास और विकास योजनाओं में तेजी के बावजूद पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं हो रही थी। लेकिन, 27 फरवरी 2002 के बाद किस्मत बदल गई। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और विधानसभा चुनावों में पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिला। मोदी 'हिंदू हृदय सम्राट' के रूप में राजनीति में उभरे।

लेकिन, मोदी को चिंता थी कि अगर उनकी पहचान यही रही तो वह गुजरात तक सीमित होकर रह जाएंगे। उनकी फिर से चुनावी जीत तब तक सुनिश्चित नहीं थी, जब तक सोनिया गांधी ने 'मौत के व्यापारी' जैसा विवादास्पद बयान नहीं दिया। वह फिर से चुनाव जीत गए। उनके मुख्यमंत्री बनने की 7वीं वर्षगांठ पर सबसे बड़ा मौका तब आया, जब टाटा मोटर्स ने नैनो कार प्रॉजेक्ट को बंगाल से गुजरात शिफ्ट करने का ऐलान किया। रातोरात मोदी 'हिंदू हृदय सम्राट' से 'विकास पुरुष' बन गए। हालांकि 'गुजरात मॉडल' की असलियत कोई भी सही से नहीं समझ पाया। 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर होने लगी, मोदी ने खुद को एक 'निर्णायक' नेता के रूप में पेश कर दिया।

देश में हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक जो सरकार बताती है और दूसरा जो लोग महसूस करते हैं। अगर सरकार कहती है कि उसने अचानक 'लॉकडाउन' के जरिए लोगों की जानें बचाईं, तो लोगों ने महसूस किया कि वे अपने खोए हुए काम को वापस नहीं पा सके। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, लेकिन साथ में बेरोजगारी भी। 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' का नारा दिया गया, जबकि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और अलगाव की भावना बढ़ी। तकनीक ने भ्रष्टाचार के कुछ तरीकों को खत्म किया, तो नए तरीके भी खोज लिए गए।

गुजरात और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के वर्षों की कहानी दो अलग-अलग नजरियों की कहानी है। शुरुआत से ही मोदी इतिहास का हिस्सा बनना चाहते थे, और अब जब उनका कार्यकाल जारी है, उन्होंने यह जगह बना ली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य के इतिहासकार इन वर्षों को कैसे समझेंगे और लोग उन्हें कैसे याद करेंगे।

नए विवाद में फंसे तेजस्वी, क्या है इसका अखिलेश कनेक्शन?

प्रवीण बागी

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भड़कना जायज है। उनपर उप-मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में लगे सामान अपने घर ले जाने के आरोप लगे हैं। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के करीब आठ माह बाद तेजस्वी यादव ने उप-मुख्यमंत्री का सरकारी आवास खाली किया है। बंगला खाली होते ही भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि एसी, सोफा, कुर्सी, पर्दे, लाइटें आदि अनेक सामान गायब हैं। आरोपों पर भड़के तेजस्वी यादव ने आरोप लगानेवालों को कानूनी नोटिस देने की धमकी दी है। तेजस्वी पर पहली बार ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। इसके पहले भी कई वर्ष पूर्व जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद वे सत्ता से बाहर हुए तो बंगला खाली करना पड़ा था। तब स्व. सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के रूप में उस बंगले में आए थे। तब मोदी ने भी पत्रकारों को बंगला दिखाते हुए आरोप लगाया था कि राजमहल के रूप में तेजस्वी ने इस बंगले को विकसित करवाया था। नियम कानून का उल्लंघन कर इसमें सुख सुविधा के साधन लगवाए गए। शौचालय में भी एसी लगवाने की बात उन्होंने बताई थी। सजावट के कई सामान विदेशों से मंगाए जाने के आरोप लगे थे। ऐसे बंगलों की साज सज्जा के लिए सरकार द्वारा तय खर्च की सीमा से अधिक खर्च किए जाने के आरोप भी लगे थे। उस समय भी तेजस्वी ने जांच कराने की चुनौती दी थी। जांच के बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। तब मीडिया ने भी क्लीन चिट मिलने की खबर उस प्रमुखता से नहीं चलाई थी, जैसी प्रमुखता से सामान गायब होने की खबर चली थी। ना ही भाजपा नेताओं ने गलत आरोप लगाने के लिए कोई खेद व्यक्त किया। अब फिर वैसे ही आरोप लगाए गए हैं। उनकी तुलना यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से की गई जिनपर चुनाव हारने के बाद सरकारी बंगला खाली करते समय अन्य समानों के साथ नल की टोटी खोल कर ले जाने के आरोप लगे थे। संयोग से तेजस्वी और अखिलेश के बीच रिश्तेदारी भी है। ऐसे आरोप घटिया राजनीति का उदाहरण है। किसी की छवि हनन के लिए ऐसे अप्रमाणित आरोप लगाया जाना राजनीति का मान्य प्रचलन बन गया है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति इसी पर टिकी है। दरअसल भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अभियुक्त होने के कारण तेजस्वी की छवि ऐसी बन गई है कि लोग उन पर लगे आरोपों पर भरोसा भी कर लेते हैं। किसी नेता पर जब भी ऐसे आरोप लगते हैं तो मीडिया बिना तथ्यों की पड़ताल के उसे ले उड़ता है। यह तरीका ठीक नहीं। इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। भवन निर्माण विभाग, जो सरकारी भवनों का केयर टेकर होता है, उसकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे भाजपा के आरोपों की पुष्टि हो। इस विवाद में एक बात सामने आई है कि ऐसे बंगलों की रंगाई-पोताई के लिए सालाना 7 से 10 लाख रुपए सरकार खर्च करती है। इसके अलावा 5 साल में फर्नीचर और साज-सज्जा के लिए 9 लाख रुपए खर्च का प्रावधान है। 5 साल के कार्यकाल में 50 लाख रुपए सिर्फ रंगाई-पोताई के लिए खर्च करना क्या भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह न्याय संगत है? यह लोकतंत्र के सामंतशाही में बदलने का परिचायक है। कोई नेता या पार्टी इसका विरोध नहीं करती। इसमें सभी की सहमति होती है। इस देश में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरे जीवन की कमाई 40 लाख नहीं होती और उनके सेवक होने का दावा करने वाले सोफा और पर्दे पर सिर्फ 5 साल में 40 लाख

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षीय यात्रा पर एक नजर

विजय कुमार

2025 की विजयादशमी पर संघ सौवें वर्ष में पहुंच रहा है। ऐसे में इस यात्रा के कुछ पड़ावों पर नजर डालना उचित होगा। डा. हेडगेवार ने संगठन को देश की राष्ट्रीय आवश्यकता कहा था। उन्होंने कोलकाता में क्रांतिकारियों और नागपुर में कांग्रेस के साथ काम कियाय पर संघ स्थापना के बाद पूरी शक्ति यहीं लगा दी। इसलिए पहले 50 साल संघ ने केवल संगठन किया। यद्यपि अन्य बहुत कुछ भी शीर्ष नेतृत्व के मन में था। दत्तोपंत ठेंगड़ी इसे प्रोगेसिव अनफोल्डमेंट कहते थे। इसके बल पर ही संघ ने हर संकट को झेला।

इस पहले दौर में स्वयंसेवकों ने कई संस्थाएं बनायीं। इनमें राष्ट्र सेविका समिति (1936), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (1949), वनवासी कल्याण आश्रम (1952), भारतीय मजदूर संघ (1955), विश्व हिन्दू परिषद (1964), भारतीय जनसंघ/भारतीय जनता पार्टी (1951), सरस्वती शिशु मंदिर/विद्या भारती (1952) आदि प्रमुख हैं। यद्यपि इनके संविधान, कोष, पदाधिकारी, कार्यक्रम आदि अलग हैंय पर प्रेरणा संघ की ही है।

संघ पर प्रतिबंध: संघ पर 1932 और 1940 में शासन ने आंशिक प्रतिबंध लगायेय पर वे ज्यादा नहीं चले। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद फिर प्रतिबंध लगा। तब शासन, प्रशासन और जनता संघ के विरोध में थी। प्रचार माध्यम सरकार के पास थे। संघ के पास अपनी बात कहने का कोई साधन नहीं था। फिर भी संघ ने सत्याग्रह से सरकार को झुका दिया।

पर फिर शाखा के साथ ही समविचारी संगठनों का विस्तार और प्रभाव बढ़ने लगा। इसीलिए जब 1975 में इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो जनता संघ के साथ रही। संघ ने फिर सत्याग्रह किया। जनता डर से चुप थी, पर चुनाव में उसका आक्रोश फूट पड़ा और इंदिरा गांधी हार गयी। यह संगठन के बल पर ही हुआ। समाज में बढ़ती स्वीकार्यता का लाभ उठाकर संघ ने संगठन को फैलाया तथा स्वयंसेवकों ने अनेक नयी संस्थाएं बनायीं।

1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सरकार ने फिर प्रतिबंध लगाया, जिसे न्यायालय ने ही खारिज कर दिया। 1975 और 1992 के प्रतिबंध से संघ के संगठन और प्रभाव

में वृद्धि हुई। उसका नाम दुनिया भर में फैल गया।

1977 के बाद: इसे हम दूसरा 50 वर्षीय कालखंड कह सकते हैं। संघ ने अनुभव किया कि हमारा काम समाज के निर्धन वर्ग में नहीं है। इनकी पहली जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। इस कारण लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं। मीनाक्षीपुरम् कांड इसका उदाहरण था। अत: सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया गया। 1989 में डा. हेडगेवार की जन्मशती पर सेवा निधि एकत्र कर हजारों पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाये गये। निर्धन बस्तियों को सेवा बस्ती कहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हजारों छोटे प्रकल्प शुरू किये। अब इनकी संख्या डेढ़ लाख से भी अधिक है। अब सैकड़ों बड़े प्रकल्प भी हैं, पर मुख्य ध्यान छोटी इकाइयों पर ही है। केवल संघ ही नहीं, तो सभी समविचारी संस्थाएं सेवा कार्य कर रही हैं। यहां से पुरुष और महिला कार्यकर्ता भी आगे आ रहे हैं।

कुछ चुनौतियां: 1947 में देश विभाजन एक बड़ी चुनौती थी। इस दौरान पंजाब और सिंध में संघ ने सीमित शक्ति के बावजूद लाखों हिन्दुओं की रक्षा की, महिलाओं की लाज बचाई और उनका पुनर्स्थापन किया। बंगाल में शक्ति कम होने से यह प्रभावी ढंग से नहीं हो सका।

1950 में प्रतिबंध हटने पर कुछ लोगों का विचार था कि निर्दोष होते हुए भी संसद या किसी विधानसभा में कोई हमारे पक्ष में नहीं बोला। अत: हमें शाखा छोड़कर केवल राजनीति करनी चाहिए पर सरसंघचालक श्री गुरुजी नहीं माने। उन्होंने कहा कि राजनीति जरूरी होते हुए भी सब कुछ नहीं है। इससे कई बड़े लोग नाराज हो गये। यद्यपि संघ ने फिर राजनीति में भी कई लोगों को भेजा, पार्टी भी बनायी, पर राजनेताओं और दलों का जो हाल है, उससे श्री गुरुजी की बात प्रमाणित हो रही है।

संगठन होने के कारण संघ तथा संघ प्रेरित संस्थाएं लगातार नयी टीम बनाकर पुरानों के संरक्षण में उन्हें पदस्थापित करते रहते हैं, पर 1968 में भारतीय जनसंघ को एक झटका लगा। दीनदयाल जी का निधन हो चुका था। जनसंघ वाले अटल बिहारी वाजपेयी को आगे लाना चाहते थे। इससे रुष्ट होकर बलराज मधोक ने पार्टी छोड़ दी, पर जल्दी ही वे समझ गये कि कुछ लोग कुछ समय के लिए कोई संस्था तो चला सकते हैं, पर संगठन नहीं। अत: वे शांत होकर फिर संघ के कार्यक्रमों में आने लगे। यद्यपि उनके अलगाव से श्री गुरुजी सहित सब स्वयंसेवकों को दुख हुआ, पर संघ में व्यक्ति नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है।

ऐसी ही एक चुनौती 2018 में विश्व हिन्दू परिषद में आयी। एक प्रभावी नेता ने अपनी नयी संस्था बना ली। यहां भी टकराव व्यक्ति और संगठन में ही था। आशा है वे भी शीघ्र ही मुख्य धारा में लौट आएंगे।

अब आगे की ओर: कभी संगठन के लिए संगठन की बात कही जाती थी, पर 50 साल संगठन और 50 साल विस्तार के बाद अब संघ समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जहां संघ का काम पुराना है, वहां परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, सामाजिक समरसता, एक मंदिर, एक शमशान, एक जलस्रोत, नागरिक कानूनों के पालन आदि का आग्रह किया जा रहा है। संघ के प्रयास से इस दिशा में भी नि:संदेह सुधार होगा। समाज में हजारों संस्थाएं और लोग अच्छे काम कर रहे हैं। संघ उन्हें भी साथ लेकर सम्मान और श्रेय देता है। संस्थागत अभिनिवेश से मुक्ति संघ की एक बड़ी विशेषता है।

यद्यपि जब से भाजपा की सरकारें केन्द्र और राज्यों में बन रही हैं, तब से संघ में बहुत भीड़ भी आने लगी है। नये लोगों का आना सुखद है, पर जो स्वार्थवश आ रहे हैं, उनसे सावधान रहना होगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे से लेकर परम वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम की इस अविराम यात्रा में बहुत काम बाकी है। निरूसंदेह अगले कुछ वर्ष में करोड़ों स्वर भारत माता की जय बोलेंगे और विश्वगुरु भारत का सपना साकार होगा।

देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचे को खतरा

मंगत राम पासला

आजादी के बाद देश के सामने आई कई कठिनाइयों और कमजोरियों के बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखा जा रहा है। इन्हीं परंपराओं का आशीर्वाद है कि बहुधार्मिक, बहुजातीय, विविध संस्कृति, भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों का हमारा देश आज भी एकजुट है और अपनी रक्षा के मामले में कई देशों से अधिक सक्षम है।

हमारी तुलना में, पाकिस्तान की धर्म-आधारित गैर-लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, जिसने गरीब लोगों को भुखमरी के कगार पर छोड़ दिया है, हमारे लिए सीखने के लिए एक बड़ा सबक है। हालांकि, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उपर्युक्त महान परम्पराओं के कारण ही भारत आज जिस उच्च स्थान पर पहुंचा है, आज उसकी नींव को कमजोर करने की तैयारी हो चुकी है। देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचे को उन ताकतों से बहुत खतरा है जो भारत को धर्म आधारित, कट्टरपंथी-पिछड़ा देश बनाकर तीव्र जाति-पाति और लैंगिक भेदभाव वाली अलोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

एक खास तरह के संगठन और उससे जुड़े संगठनों के नेता आए दिन अपने ही देशवासियों के लिए काल्पनिक खतरा पैदा कर बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय को अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए उकसाते हैं। ये बदनाम समूह एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को देशद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, घुसपैठिया, भारतीय संस्कृति का दुश्मन और अन्य बातें बोलकर समाज की नजरों में नफरत का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था तभी मजबूत रह सकती है जब प्रत्येक नागरिक को सरकार से असहमत होने का अधिकार हो तथा लिखने, बोलने एवं अन्य माध्यमों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। साथ ही कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी को सरकार के दबाव एवं हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निर्भीक होकर पूरा करना होगा।

इसके अलावा, प्रत्येक संस्था और सरकारी पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

ऐसे ढांचे में, लोगों के राज्य का चौथे स्तंभ, यानी 'प्रिंटिंग और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया' की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया को भी इसी भावना से संचालित किया जाना चाहिए। यदि किसी भी लोक राज्य संरचना में लोगों के दिल और दिमाग सभी प्रकार के नाजायज दबाव और प्रतिशोध से मुक्त नहीं हैं, तो लोकतंत्र की वास्तविक अवधारणा गायब हो जाती है।

इन सबके अलावा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ताकि देश के सभी नागरिक बिना किसी लालच, भय, दबाव और भेदभाव के अपने विवेक के अनुसार मतदान कर सकें। तदनुसार, वे अपने वोट के अधिकार का उपयोग करके अपनी पसंद की सरकार या प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसके लिए देश के संविधान में आवश्यक कानून भी है और प्रक्रिया भी दर्ज है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करते हुए देश की नींव को बनाए रखना और मजबूत करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हालांकि, यह बेहद चिंता का विषय है कि देश में सभी स्तरों के चुनावों में लोकतांत्रिक ढांचे की नींव लगातार कमजोर हो रही है।

लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 95 लाख, विधानसभा के लिए 40 लाख और पंचायत चुनाव के लिए 40 हजार रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है। लेकिन क्या लोकसभा और निचली संस्थाओं में ऐसा हो रहा है? मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवारों द्वारा नशीली दवाओं, धन और उपहारों के वितरण जैसी अवैध गतिविधियों पर बेशुमार धनराशि खर्च की जाती है। शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से पैसा खर्च करते हैं।सत्ता हासिल करने के लिए धर्म-जाति-क्षेत्र-भाषा आदि अंधराष्ट्रवादी मुद्दों का दुरुपयोग कर समाज में फूट डालना वर्तमान चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि देश की स्वशासी संस्था, भारत निर्वाचन आयोग वास्तव में निर्वाचन प्रणाली की निष्पक्षता और दक्षता के प्रति मतदाताओं का विश्वास कायम रखने में विफल रही है।

अफसोस की बात है कि शासकों और नौकरशाहों के इस व्यवहार के कारण और गुरबत की हत्या के कारण पैदा हुए राजनीतिक-वैचारिक पिछड़ेपन के चलते, आम जनता के एक बड़े हिस्से ने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए इन सभी अवैध और अपमानजनक प्रथाओं को स्वीकार कर लिया है। जब किसी गांव में एक अमीर आदमी सर्वसम्मति के नाम पर सरपंच बनने के लिए 2 करोड़ रुपए की बोली लगाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अमीर लुटेरे' केंद्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक हर सार्वजनिक संस्थान को नियंत्रित करते हैं। यदि यह रकम सच्चे परिश्रम से अर्जित की गई हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे धन का स्रोत काले कारोबार पर आधारित लूट की कोई मशीनरी है। इतना खर्च करके जीत हासिल करने वाले किसी भी व्यक्ति से जनसेवा की उम्मीद करना या ईमानदार बनकर अपनी उचित जिम्मेदारी निभाने के बारे में सोचना 'मूर्खों के स्वर्ग में रहने' के बराबर है।

प्रशासनिक मशीनरी, जिसका आज पूरी तरह से निजीकरण हो चुका है, आंखें मूंद कर संवैधानिक मानदंडों और अपने आकाओं यानी शासकों के सभी आदेशों की धज्जियां उड़ाती है। राजनीतिक दल भी समान रूप से दोषी हैं। पंजाब में पंचायत चुनावों के नामांकन भरते समय जिस तरह की गुंडागर्दी और नौकरशाही की सरकार समर्थक प्रवृत्ति देखी गई, उससे साबित होता है कि पंचायत चुनाव महज एक दिखावा और बड़ी भूलों पर आधारित धोखाधड़ी है। यह घटना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आज सभी लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकतें आम लोगों को लामबंद कर रही हैं ताकि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था लागू हो।

अनूठा 'हरियाणवी मिजाज' बना नई राजनीतिक प्रयोगशाला

ऋतुपर्ण दवे

सच है कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा की हार की चर्चा हरियाणा की जीत के आगे दब गई। यह भी सही है कि कांग्रेस दिख रही जीती बाजी को आपसी कलह, गुटबाजी और सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ के चलते हार गई। लेकिन हैरानी है कि इस पर कांग्रेस में मंथन, चिंतन, विश्लेषण के पहले ही दौर में एक बार फिर वही दिखा जो अब तक होता रहा। कुछ को आगे कर बाकियों को साधने, समझाने की कवायद में ही शीर्ष नेतृत्व का दम-खम चुनाव के दौरान काया होता रहा। पहली ही समीक्षा बैठक में क्षत्रपों को न बुलाना, क्या संदेश दिया समझ आता है। यह लाचारी है या मजबूरी, नहीं पता। इसका असर उन राज्यों पर कांग्रेस के दावों पर जरूर पड़ेगा, जहां पर चुनाव होने हैं। यदि कांग्रेस संगठन ने यही तेवर चुनाव के दौरान दिखाए होते तो नतीजे अलग आते। दरअसल एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब

बेहद सतर्क और होशियार मतदाताओं ने भी साबित कर दिखाया कि जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। चाहे बीता लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा राज्य का हालिया चुनाव।अपनी बेलाग बातों और खास अंदाज के लिए चर्चित हरियाणा ने लोकतंत्र को बड़ा संदेश भी चाहे-अनचाहे दे दिया कि मतदाताओं की परिपक्वता और मन-मस्तिष्क की थाह लेना उतना भी सहज नहीं जितना चुनाव के दौरान दल, उम्मीदवार, समीक्षक मान बैठते हैं। करीब 14 सीटों पर अपनों की आजाद उम्मीदवारी तो कुछ क्षेत्रीय दलों की दावेदारी ने ही भाजपा का रास्ता साफ किया। 'आप' के साथ गठबंधन न करना भी इस हार की तमाम वजहों में खास है। हां, जहां-जहां लड़ाई कांग्रेस-भाजपा में आमन-सामने की थी बेहद रोचक-रोमांचक थी। 36 बिरादरी की चर्चा फिर खूब हुई जिसका दोनों को समर्थन मिला। जहां भाजपा को ब्राह्मण, राजपूत, गैर जाट ओ.बी.सी., पंजाबी-खत्री के मत एकमुश्त मिले वहीं कांग्रेस पर जाट, गुर्जर, जाटव, मुस्लिम और सिखों ने खूब भरोसा जताया। हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का सूपड़ा साफ होना भी बताता है कि उनका भविष्य चिंताजनक है! कांग्रेस के मुद्दे यकीनन कमजोर नहीं थे इसीलिए पिछली बार से 6 सीटें अधिक आईं। लेकिन करीब 3 प्रतिशत गैर जाट मत भाजपा की ओर रुख करने से माजरा बदला और फायदा 8 सीटों पर मिला। हरियाणा के नतीजों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के घोषित लक्ष्य नहीं हासिल कर पाने के घाव पर मरहम का काम जरूर किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि महाराष्ट्र-झारखंड और उप-चुनावों में चुनौतियां घटेंगी। भले ही हरियाणा में हार से कांग्रेस कमजोर होगी और संभव है कि गठबंधन में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। लेकिन संगठन को लेकर पार्टी और गठबंधन कितना चेतेंगे यही देखने लायक होगा। इसकी शुरूआत हरियाणा से कर शायद कांग्रेस कोई बड़ा संदेश दे? भले ही नतीजे चौंकाने वाले कहलाएं लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भाजपा खुद भी इतना आश्वस्त नहीं थी। यह तो नतीजों के बाद मौके पर भाजपा ने चौका लगाया और माइक्रो मैनेजमैंट को श्रेय देकर देश भर के कार्यकर्त्ताओं में जोश भरते हुए मोदी मैजिक को रिफ्रैश कर दिया। उत्साह के लिहाज से भाजपा का खुश होना जायज है लेकिन आगे महाराष्ट्र, झारखंड सहित 6 राज्यों की 28 सीटों जिनमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पंजाब की 4, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उप-चुनाव होने हैं। इसके बाद नए साल में दिल्ली, बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। ज्यादातर में क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकत है। यही चुनौती इंडिया गठबंधन और एन.डी.ए. को भी है क्योंकि तब तक भाजपा में हरियाणा का मरहम तो कांग्रेस में हार के गम का असर कम हो जाएगा। यकीनन देश की राजनीति रोचक मोड़ पर है। ले-देकर अनूठा हरियाणवी मिजाज देश में नई राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है।

बैंकिंग सेक्टर में भी इस तरह बन सकते हैं लीडर

किसी भी सेक्टर में या किसी भी ऑफिस में, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को उनका काम करने में मार्गदर्शन देते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा बॉस ही लीडर हो, कोई और भी लीडर हो सकता है। लीडरशिप का गुण ऑफिस में आपके व्यवहार में प्रतिबिंबित हो ही जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी हर ब्रांच में एक लीडर की जरूरत होती है और बैंक ऑफिसर्स की भर्ती करने वाले इंटरव्यू पैनल ऐसे ही लीडर की तलाश में होते हैं। किसी बैंक ब्रांच में दूसरों का नेतृत्व करने के लिए कई गुणों की जरूरत होती है। कारण यह कि बैंक में किसी भी दिन ऐसी कई स्थितियां बन सकती हैं, जिनमें संभव है कि ब्रांच मैनेजर भी न समझ पाए कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ब्रांच में कोई तो हो, जो रास्ता दिखा सके। एक बैंकर को अच्छा लीडर बनाने वाले गुण इस प्रकार हैं –

जरूरी नहीं कि हमेशा बॉस ही लीडर हो, कोई और भी लीडर हो सकता है। लीडरशिप का गुण ऑफिस में आपके व्यवहार में प्रतिबिंबित हो ही जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी हर ब्रांच में एक लीडर की जरूरत होती है और बैंक ऑफिसर्स की भर्ती करने वाले इंटरव्यू पैनल ऐसे ही लीडर की तलाश में होते हैं। किसी बैंक ब्रांच में दूसरों का नेतृत्व करने के लिए कई गुणों की जरूरत होती है।

त्वरित बुद्धि

यह सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी पैसों संबंधी कोई समस्या उठ खड़ी होती है, तो अक्सर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। आखिर सवाल रुपए-पैसों का जो है! ऐसी स्थिति में एक लीडर की त्वरित बुद्धि के चलते उसके समक्ष एक नहीं, अनेक उपाय उठ खड़े होंगे। तब वह उनमें से श्रेष्ठ उपाय को चुनकर लागू करेगा।

ठंडा दिमाग

लीडरशिप के लिए यह बहुत जरूरी होता है। बैंकिंग में आपका पाला कई लोगों से पड़ेगा और सब एक जैसे नहीं होंगे। ऐसे भी लोग होंगे, जो बैंक में आकर आपसे या स्टाफ के किसी अन्य सदस्य से बहस करेंगे लेकिन ऐसे में आपको अपना संतुलन नहीं खोना है। याद रखें, वह व्यक्ति तो अपना काम कराकर चला जाएगा लेकिन यदि आप गरम दिमाग से दिन भर काम करेंगे, तो आपसे जरूर कोई-न-कोई गलती हो ही जाएगी! इसलिए लीडर के लिए हर हाल में शांत बने रहना जरूरी है। वैसे भी ग्राहक तो ग्राहक होता है और बैंक कर्मचारी के तौर पर आपका काम उसकी सेवा करना ही है।

लचीलापन

लीडर होने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी मर्जी से लोगों को हांक लेंगे। यह संभव नहीं कि किसी के पास हर समस्या का समाधान हो। हो सकता है कि आपके पास किसी समस्या का समाधान न हो लेकिन किसी और के पास यह होगा। आपको उस शख्स की मदद लेनी होगी ताकि काम हो सके। एक सच्चा लीडर इतना लचीलापन हमेशा रखता है।

अच्छे संबंध रखें

बैंकिंग में यह बहुत जरूरी है क्योंकि बैंकिंग का व्यवसाय मूल रूप से विश्वास पर ही टिका होता है। आपको ब्रांच के हर कर्मचारी तथा ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने होते हैं। इससे ब्रांच में माहौल सकारात्मक बना रहता है।

दूसरों का सहारा बनें

गलती हर किसी से होती है और बैंकिंग में होने वाली गलती पैसे से जुड़ी ही होगी। बैंकर के रूप में, आपको जरूरत के समय अपने साथियों का साथ देना चाहिए। इससे उनकी नजरों में आप सच्चे लीडर होंगे।

लगन व परिश्रम

लीडर होने का मतलब है दूसरों के लिए मिसाल पेश करना और लगनशील व परिश्रमी होने की मिसाल से बेहतर क्या हो सकता है? जब साथी आपको मेहनत कर परिणाम प्राप्त करते देखेंगे, तो वे भी ऐसा ही करने को प्रेरित होंगे।

औरों से दो कदम आगे रहें

बैंकिंग जैसे प्रतिस्पधी क्षेत्र में यह बहुत जरूरी है कि लीडर अपनी सोच और अपने व्यवहार में दूसरों से हमेशा दो कदम आगे रहे। तभी तो वह अपने संस्थान को आगे ले जा पाएगा।

फोटोग्राफी की इन शाखाओं में बना सकते हैं शानदार करियर

फोटोग्राफी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी बात को कहने में जहां हजार शब्दों की जरूरत पड़ सकती है, वहीं एक फोटो हजार शब्दों को बयां कर देता है। फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए इस फील्ड में अनुभव के साथ इसका शौक होना भी बहुत जरूरी है। यह क्षेत्र न सिर्फ अच्छा पैसा देता है, बल्कि ग्लैमर से भी जुड़ा हुआ है।

क्या आपमें है धैर्य?

इस क्षेत्र में सफल होने के लिए एक मूलमंत्र है धैर्य। अच्छे क्लिक के लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है। फिर चाहे आप किसी भी माहौल में काम कर रहे हों। तनावपूर्ण माहौल हो या भीड़ भरे इलाके, फोटोग्राफर को अच्छा परिणाम देने में सक्षम होना पड़ता है। फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर के लिए अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। उसके लिए उसका कैमरा ही उसकी आंखें है। इसके अलावा, फ्रीलांस फोटोग्राफर या व्यवसायिक फोटोग्राफरों के पास तकनीकी कौशल के साथ व्यापारिक समझ भी होनी चाहिए। तकनीकी पहलू लाइटिंग, लैंस, रिफ्लेक्टर, फिल्टर और सेटिंग्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ही फोटोग्राफर किसी पिक्चर को कैप्चर करते हैं। इसी के साथ अच्छी फोटो खींचने के लिए कई चीजों के समायोजन की जरूरत होती है, जैसे कैमरे की क्वॉलिटी, सब्जेक्ट, लाइटिंग, फोटोग्राफर का कौशल आदि। डिजिटल कैमरों में इलेक्ट्रॉनिक मेमरी का इस्तेमाल किया जाता है। इन तकनीकों की जानकारी होना आज के समय में जरूरी है।

फोटोग्राफी की शाखाएं

फोटोग्राफी की कुछ खास शाखाएं हैं, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये इस प्रकार हैं –

विज्ञापन/ फैशन – विज्ञापनों और विज्ञापन एजेंसियों के कार्य के लिए कुशल फोटोग्राफरों की जरूरत होती है। फैशन फोटोग्राफी काफी हद तक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के समान ही होती है लेकिन इसमें तकनीक से ज्यादा परिधानों को उजागर करने की क्षमता जरूरी होती है।

कला/ फिल्म – आजकल किसी भी फिल्म की मेकिंग से लेकर उसके प्रदर्शन तक सारी गतिविधियां कैमरे में कैद की जाती हैं। इसके लिए हाई क्वॉलिटी और हाई रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है।

साइंस/ मेडिकल/ तकनीक – इन क्षेत्रों में कार्यरत फोटोग्राफर कला से ज्यादा महत्व वस्तुपरक दृष्टिकोण को देते हैं, जिससे तथ्य को समझने में आसानी हो सके। फॉरेन्सिक लैब हो या वारदात का स्थान, सभी जगह कई एंगलों से फोटो खींचने होते हैं।

फोटो जर्नलिज्म – अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो तुरंत घटनास्थल तक पहुंचने के साथ ही सबसे पहले प्रेस या स्टूडियो तक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको ही निभानी होती है। फोटो जर्नलिज्म में फोटो की श्रृंखलाओं के माध्यम से किसी विषय या घटना के बारे में स्टोरी फाइल की जाती है। आज के डिजिटल दौर में विश्व की प्रमुख घटनाओं को फोटो के माध्यम से कवर करने का रुझान तेजी से बढ़ा है।

कैसे करें शुरूआत?

बारहवीं या ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में प्रवेश लिया जा सकता है। इस कोर्स को सरकारी या निजी स्तर पर कई संस्थान कराते हैं। कोर्स करने से पहले बेसिक फोटोग्राफी का ज्ञान हासिल कर लेना अच्छा रहता है। बेहतर होगा कि एक डिजिटल कैमरा लेकर इसकी शुरूआत कर दी जाए। जब आपको लगे कि आप इस कोर्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो फिर डिजिटल एसएलआर खरीदकर प्रोफेशनली इससे जुड़ जाएं।

प्रशिक्षण भी अहम

फोटोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए किसी अच्छे संस्थान से फाइन आर्ट्स या मास कम्युनिकेशन कोर्स करके अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वहीं मोशन फोटोग्राफी का प्रशिक्षण फिल्म एवं टेलीविजन संस्थानों द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश लेना जरूरी है। इनमें फोटोग्राफी कला का अध्ययन कराया जाता है। इससे आपको मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जब आपको लगे कि आप पर्याप्त सक्षम हो गए हैं, तो किसी एक्सपर्ट फोटोग्राफर के साथ काम कर बारीक चीजों को भी सीख सकते हैं। फिर उच्च शिक्षण संस्थान की ओर रुख कर सकते हैं। यदि यह तरीका न भाए, तो दूसरे तरीके से फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जैसे कोर्स में प्रवेश लें। इसमें आपको फोटोग्राफी मुख्य कोर्स के तौर पर पढ़ाई जाएगी। ध्यान रहे, प्रशिक्षण आपको तकनीकी पहलुओं की जानकारी दे सकता है लेकिन नए विचार और व्यक्तिगत स्टाइल तो स्वयं ही विकसित करनी होती है। व्यवहारिक ज्ञान यहां सबसे जरूरी होता है।

इन टिप्स को अपनाकर बन सकते हैं एक अच्छा मैनेजर

किसी भी संस्थान में एक मैनेजर की अहम भूमिका होती है। अगर आप भी अपने करियर में आगे बढ़ते हुए इस पद पर पहुंच गए हैं या पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र के अलावा और भी चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स की असली परीक्षा यही देनी होती है। एक लीडर के रूप में आप सभी सफल हो सकते हैं जब आपके कर्मचारी आपके साथ खुश, प्रेरित और उत्साहित महसूस करें।

कर्मचारियों को प्रेरित करना

अगर आप अपनी टीम का सम्मान करेंगे तो वे आपका सम्मान करेंगे। आपको उनकी हर छोटी-बड़ी चीजों का एप्रिशियेट करना होगा। उनसे अपने काम की ही फीडबैक न लेते रहें, बल्कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

फील गुड कराएं

कर्मचारियों से केवल काम लेना है, ऐसी सोच आपके अच्छे मैनेजर बनने का गुण नहीं है। एक सफल मैनेजर में अपने कर्मचारियों की अच्छी बातों और क्षमताओं को पहचाने की समझ होती है। उनका मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें ऐसा माहौल दें कि वे बेहिचक काम कर सकें।

पीठ पीछे भी प्रशंसा

आपको उनके काम, व्यवहार, उदारता की तारीफ उनके सामने तो करनी ही चाहिए। साथ ही आपको उनके पीठ पीछे भी तारीफ करना चाहिए। एक कर्मचारी जो जानता है कि उसकी कितनी प्रशंसा की जाती है तो वह ज्यादा मेहनत करेगा, अपने काम में ज्यादा आनंद लेगा और इस मानसिक खुशी को वह दूसरे कर्मचारियों के साथ बांटेगा।

जिम्मेदारी सौंपे

आप एक मैनेजर है क्योंकि आप अपने काम में एक्सपर्ट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारा काम खुद करना है। आपको यह समझ होनी चाहिए कि कौन सा काम,कौन सा कर्मचारी बखूबी पूरा कर सकता है। आपको अपने कर्मचारी को सीखने और नए अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे-धीरे जैसे आप उनकी सक्षमता और कमजोरियों को समझने लगें उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी के काम सौपें।

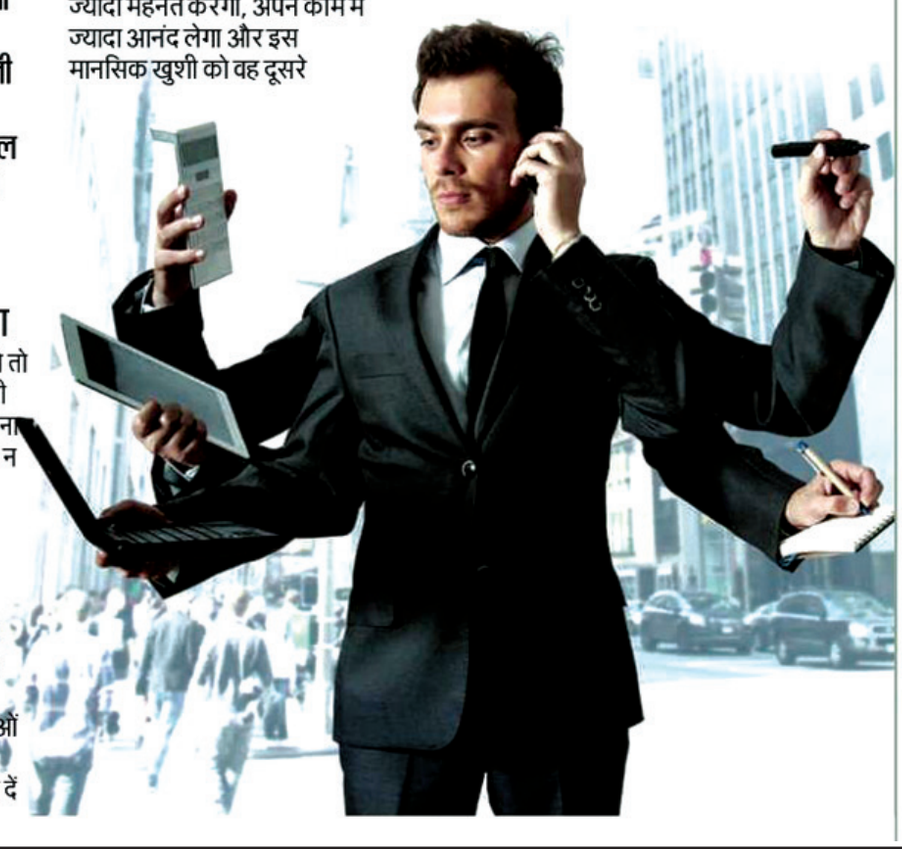

मैथ्स में है रूचि तो इन क्षेत्रों में बना सकते हैं करियर

गणित मनुष्य के ज्ञान की एक अत्यधिक उपयोगी तथा आकर्षक शाखा है। इसमें अध्ययन के कई विषय शामिल हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गणित की एक सुदृढ़ परंपरा रही है और आज भी यहां गणित में विश्व स्तर के अनुसंधान करने वाले अनेक संस्थान हैं। गणनाओं में रुचि रखने वाले युवा बड़ी संख्या में गणित को करियर के रूप में चुनते हैं। गणित लगभग सभी वैज्ञानिक अध्ययनों का एक अनिवार्य अंग है। वैज्ञानिक गणित का उपयोग प्रयोगों की रूपरेखा बनाने, सूचना का विश्लेषण करने, गणित के सिद्धांतों द्वारा अपने निष्कर्ष उचित रूप में व्यक्त करने तथा इन निष्कर्षों के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान जैसे विषय तो गणित पर ही निर्भर हैं। सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग आदि भी गणित की ही शाखाओं पर निर्भर होते हैं।

भारत में 135 से भी अधिक विश्वविद्यालय गणित से जुड़े कोर्स चलाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय शुद्ध गणित (प्योर मैथमेटिक्स) व अनुप्रयुक्त गणित (अप्लायड मैथमेटिक्स) में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। आप कुछ स्थानों पर चलाए जाने वाले एकीकृत एमएससी पीएचडी डिग्री कोर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यूं देश में स्नातक स्तर पर गणित की शिक्षा देने वाले दो विश्व स्तरीय संस्थान हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), बेंगलुरु तथा चेन्नाई गणित संस्थान (सीएमआई), चेन्नाई। आईएसआई से गणित व कम्प्यूटर विज्ञान में बी. मैथ्स डिग्री तथा सीएमआई से गणित की बीएससी डिग्री की जा सकती है। इनमें प्रवेश प्रत्येक वर्ष मई के अंत में देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली एक लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। ये दोनों संस्थान ऐसे विद्यार्थियों को भी अपने यहां प्रवेश देते हैं, जो इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलिंपियाड (आईएनएमओ) में पास होते हैं या किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) अध्येता होते हैं। गणित में विशेषज्ञतापूर्ण कोर्स चलाने वाले देश के अन्य प्रमुख संस्थान इस प्रकार है –

- औद्योगिक गणित में पाठ्यक्रम पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में उपलब्ध है।
- न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स पाठ्यक्रम मदुरै कामराज विश्वविलय, मदुरै में उपलब्ध है।
- गणितीय अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में उपलब्ध है।

इसके अलावा एमएससी व पीएचडी कोर्स के लिए देश के प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं – टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई। लिखित परीक्षा तथा उसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर), पुणे/ मोहाली/ कोलकाता/ तिरुवनंतपुरम/ भोपाल तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर में भी गणित में एकीकृत एमएससी डिग्री कोर्स उपलब्ध है। आईआईएसईआर विद्यार्थियों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देता है, जबकि एनआईएसईआर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट (एनईएसटी) के माध्यम से प्रवेश देता है।

हैदराबाद विश्वविलय द्वारा गणित में एकीकृत एमएससी पाठ्यक्रम चलाया जाता है। यह विश्वविद्यालय जून के आरंभ में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देता है।

विषय एक संभावनाएं अनेक

गणित तथा इससे जुड़े प्रमुख करियर इस प्रकार हैं

गणितज्ञ

गणितज्ञों को गणित का अध्ययन अथवा अनुसंधान करना होता है। वे गणित के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं।

शिक्षण

गणित के शिक्षकों की मांग कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। गणित पूरी स्कूली शिक्षा में एक मुख्य विषय होता है। यदि आपमें संख्याओं के प्रति गहरा आकर्षण है और विद्यार्थियों **को पढ़ाने में आपकी रुचि है, तो आप शिक्षण** के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में **कार्य** करने वाले गणितज्ञों का अध्यापन तथा अनुसंधान में खास योगदान होता है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों **की** न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में धूम मची हुई है। वैश्विक आईटी इंडस्ट्री भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को **रोजगार देने** के लिए बाहें फैलाए **खड़ी है**। सॉफ्टवेयर इंजीनियर **सॉफ्टवेयर** के प्रयोग तथा उनकी प्रणाली का सृजन, परीक्षण, विश्लेषण व मूल्यांकन करने के लिए कम्प्यूटर विज्ञान और गणितीय विश्लेषण के सिद्धांतों को कार्यान्वित करते हैं।

बैंकिंग

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के चलते बैंक तेजी से अपनी **शाखाएं** बढ़ा रहे हैं, जिससे इस **क्षेत्र** में रोजगार के हजारों नए **अवसर** निर्मित हो रहे हैं। गणित में महारथ रखने वाले युवा बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट

उदारीकरण के बाद भारतीय **अर्थव्यवस्था** के तीव्र विकास के चलते अकाउंट्स तथा फाइनेंस के क्षेत्र में करियर ने खूब **लोकप्रियता** अर्जित की है। इस **क्षेत्र** में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक **अत्यधिक** प्रतिष्ठित करियर **विकल्प** है। मैथ्स व कॉमर्स में रुचि रखने वाले युवा इस क्षेत्र में बढ़िया करियर बना सकते हैं।

कम्प्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट

कम्प्यूटर सिस्टम्स एनालिस्ट के लिए सॉफ्टवेयर, अनुसंधान, शिक्षा, सिक्यूरिटी, बैंकिंग, **अर्थशास्त्र**, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिकी, तकनीकी शाखाओं आदि में **रोजगार** के ढेरों अवसर हैं। **अधिकांश** सिस्टम्स एनालिस्ट लागत-लाभ व निवेश पर मुनाफा का विश्लेषण तैयार करने के लिए विशिष्ट प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियों पर कार्य करते हैं और मैनेजरों को यह **निर्णय लेने** में सहायता करते हैं कि या प्रस्तावित टेक्नोलॉजी वित्तीय दृष्टि से कारगर होगी या नहीं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम ने एनएसजी के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के स्थापना दिवस के मौके पर इस आकस्मिक तैनाती बल के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश की सुरक्षा में इसके योगदान पर हर देशवासी को नाज है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एनएसजी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत उन सभी एनएसजी कर्मियों को सलाम करता है, जो राष्ट्र की रक्षा करने में अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। खतरों के खिलाफ हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। उनकी वीरता और उनके पेशेवराना अंदाज का कोई सानी नहीं है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण विरोधी क्रिया कलापों में इसके जवान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग करते हैं। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का उपयोग किया जाता है।

इस्लामाबाद में जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की जा रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आतंकी घटनाएं जारी रहेंगी तो फिर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस तरह जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को उसी के घर में लताड़ लगाई। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर दिए अपने संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हम ऐसे समय मिल रहे हैं, जब दुनिया संकटों से गुजर रही है। दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं और उनका पूरे विश्व पर नकारात्मक असर हो रहा है। कोरोना महामारी ने कई विकासशील देशों को बुरी तरह प्रभावित किया। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता और वित्तीय कमजोरी विकास को प्रभावित कर रही है।

चुनाव के ऐलान के बाद महायुति सरकार ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। आरपीआई (ए) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार की लाडली बहिन जैसी योजनाओं को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से हमारे विरोधी चकित हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार परिवर्तनकारी योजनाएं लेकर आयी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में महायुति के संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन विकास विरोधी दूरदृष्टि से काम करता है। यूबीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए, महायुति नेताओं ने कहा कि पूर्व सीएम राज्य में परियोजनाओं में देरी कर रहे थे।

बिहार में उपचुनाव के लिए जन सुराज ने उतारे अपने उम्मीदवार

पटना। बिहार में चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जन सुराज ने अपने उम्मीदवार का एलान किया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का एलान किया है। एलान करते हुए बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। नाम का एलान होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने कहा कि अबतक समाज से लिया है, अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। इसी विश्वास के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। इस उपचुनाव में 'जन सुराज' अपने उम्मीदवार की घोषणा करने वाली पहली पार्टी है, जबकि अन्य दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। प्रशांत किशोर ने इससे पहले 02 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी की घोषणा की थी। बिहार की रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। ये

'6जी' मानकों व विनियमों में सभी के लिए समावेशिता सुनिश्चित होनी चाहिए: सिंधिया

नई दिल्ली। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि 6जी से संबंधित मानकों तथा नियमों से सभी के लिए समावेशिता और सामर्थ्य सुनिश्चित होना चाहिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) में अंतरराष्ट्रीय 6जी संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर सिंधिया ने कहा कि चूंकि 6जी के लिए मानक तय किए जा रहे हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग में अपनी सिद्ध क्षमताओं को देखते हुए भारत के पास जबरदस्त अवसर हैं। मंत्री ने कहा, '' हमारे 6जी मानक जो अभूतपूर्व गति, कम विलंबता और परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों की विशेषता रखते हैं...सभी के लिए समावेशी, सुलभ व किफायती होने चाहिए और केवल तभी यह समग्र मानवता के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।'' सिंधिया ने 6जी अवसर का लाभ उठाने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया।

उमर अब्दुल्ला ने संभाली जम्मू-कश्मीर की कमान

केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की कमान संभाल ली। 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार बनने से लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि नई सरकार जन अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है। हम आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी।

शपथ ग्रहण समारोह में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुक सांसद कनिमोझी, माकपा नेता प्रकाश करात, भाकपा नेता डी राजा, सांसद सुप्रिया सुले और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आदि मौजूद थे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ने गठबंधन के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। इस मुद्दे पर नेशनल कांफ्रेंस ने कहा है कि दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को मात्र एक कैबिनेट मंत्री पद देना चाह रहे थे जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में मात्र छह सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने कहा है कि वह मंत्रिपरिषद में तब तक शामिल नहीं होगी जब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता।

हम आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में शामिल किये गये लोगों में जावेद राणा, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा, सुरिंदर चौधरी और सकीन इतू शामिल हैं। सतीश शर्मा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल की थी। उन्होंने जीत हासिल करने के बाद नेशनल कांफ्रेंस को समर्थन देने की घोषणा की थी। सुरिंदर चौधरी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है उन्होंने नौशेरा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को मात दी थी।

हम आपको यह भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के संस्थापक शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पठानी सूट और कोट पहने 54 वर्षीय अब्दुल्ला ने पार्टी संस्थापक के स्मारक पर फूल चढ़ाए। इस बारे में नेशनल कांफ्रेंस ने कहा, ''जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पूर्व उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल में अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के स्मारक पर दुआ मांगी।''

हम आपको बता दें कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के 2019 में निरस्त होने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि उमर अब्दुल्ला ही 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला आखिरी मुख्यमंत्री थे। हम आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे के दौरान यहां की विधानसभा का कार्यकाल छह वर्ष का होता था। शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करके शुरू करना होगा।

अनिल विज ने रखा नाम का प्रस्ताव, हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सिंह

आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। पंचकूला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया। भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी का नाम रखा था। सैनी गुरुवार को पंचकूला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

शाह ने कहा कि बैठक में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सिंह सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूं। नायब सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गृहमंत्री अमित शाह रात को चंडीगढ़ के ललित होटल में रुकेंगे। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा राजभवन में मीटिंग लेंगे। भाजपा ने अपने सभी 48 विधायकों को अगले दो दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश जारी किए हैं। होटल ललित और हरियाणा राजभवन सेक्टर-6 में काफी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।

वहीं होटल हयात में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड और पुडुचेरी के सीएम शामिल हैं। बैठक में शामिल होने नायब सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। पार्टी में नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर कोई शक नहीं है। भाजपा ने उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यहां तक कि अमित शाह ने चुनाव से पहले पंचकूला में कार्यकर्ताओं की बैठक एलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में नायब सिंह सैनी को ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते आए हैं। एतिहासिक जीत के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में नायब सिंह सैनी का कद भी बढ़ा है। ऐसे में उनके नाम को लेकर कोई संशय नहीं है। होडल से भाजपा विधायक हरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं।

इसलिए आना पड़ा अमित शाह को

बीते मार्च में मनोहर लाल को हटाकर विधायक दल की बैठक में जब नायब सिंह सैनी का नाम रखा गया तो अनिल विज नाराज हो गए थे। वह बैठक से बाहर निकल गए थे। चुनाव से पहले अनिल विज मुख्यमंत्री की दावेदारी जता चुके हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी समय-समय पर दावेदारी जताते रहे हैं। लिहाजा इस तरह के विवादों से बचने के लिए शाह को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले 2022 में शाह यूपी में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे और योगी के नाम पर मुहर लगाई गई थी।

नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा

विधायक दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल को अगले दिन शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों की सूची सौंपी जाएगी। उसके बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता और मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्तूबर को पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में होगा।

समारोह में पीएम समेत 37 लोग विशेष अतिथि होंगे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया, समारोह में पीएम मोदी समेत 37 विशेष अतिथि होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री, एनडीए घटक दल के राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री शामिल हैं। हम लोग सभी के संपर्क में हैं और सौ फीसदी हाजिरी पूरी होगी।

उन्होंने बताया 17 को करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग एक बजे तक समारोह संपन्न हो जाएगा। उधर, शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। किसी को बाहर से आ रहे मुख्यमंत्रियों के स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो किसी को केंद्रीय मंत्रियों को स्टेज पर लाने तक की ड्यूटियां लगाई गई हैं।

शपथ के साथ ही 24 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत-न्यूजीलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द

बेंगलुरु। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच शुरू नहीं हो पाया। सुबह से ही लगातार बारिश के कारण ग्राउंड को कवर करके रखा गया था। इसके बड़ा खेल शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था। टॉस तक नहीं हो पाया।

नियमित अंतराल पर अंपायरों और ग्राउंड स्टाफ ने स्थिति का जायजा लिया लेकिन बारिश काफी देर तक होती रही। पहला और दूसरा सेशन बारिश से धुल गया और अंतिम सेशन में खेल आयोजित कराने के लिए अंपायरों ने एक बार कवर्स हटाकर मामला देखा।

दूसरे सेशन का खेल नहीं होने के बाद जब कवर्स हटाए जा रहे थे, उस समय उम्मीदें जगी थी कि अब कुछ हो सकता है। इसके बाद फिर से बारिश ने इन उम्मीदों को तोड़ दिया। तुरंत कवर्स को वापस लगाना पड़ा और अंपायरों ने पहले दिन का गेम रद्द कर दिया।

आज बेंगलुरु में ऑरेंज अलर्ट था और स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। मंगलवार से ही बेंगलुरु में बारिश हो रही है। अब बीसीसीआई ने अपडेट दिया है कि गुरुवार को टेस्ट के दूसरे दिन 98 ओवर गेंदबाजी होगी टॉस पौने नौ बजे होगा, जबकि पहली गेंद नौ बजकर 15 मिनट पर फेंकी जाएगी।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को आठ टेस्ट और खेलने हैं और उसमें से पांच जीतने हैं, तभी जाकर टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। कीवी टीम केन विलियम्सन के बिना उतरेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 319 अंक गिरा निफ्टी 25 हजार के नीचे बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे निराशाजनक रहने और विदेशी निवेशकों के घरेलू मार्केट से लगातार पैसा निकालने के चलते बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज गिरावट के साथ 81,646.60 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान 81,358.26 से 81,932.15 अंक के बीच झूलने के बाद सेंसेक्स 0.39 प्रतिशत या 318.76 अंक की गिरावट लेकर 81,501.36 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.34 प्रतिशत या 86.05 अंक की गिरावट लेकर 24,971.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा 2.87 प्रतिशत की गिरावट लेकर बंद हुआ। इसके अलावा अदाणी पोर्ट्स, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स के शेयर प्रमुख रूप से गिरावट में रहे।

बीईएमएल को मिला 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट

नईदिल्ली। सरकारी कंपनी बीईएमएल को रू. 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत दो हाई-स्पीड ट्रेन सेट्स का डिज़ाइन, निर्माण और कमीशनिंग किया जाएगा। यह पहली बार है जब इस तरह का काम देश में ही किया जाएगा। यह ठेका चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) द्वारा दिया गया है। 'बिज़नेस स्टैंडर्ड' ने 6 जून को रिपोर्ट किया था कि रेल मंत्रालय ने आईसीएफ को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली दो ट्रेन सेट्स बनाने का निर्देश दिया था। इसके लिए आईसीएफ ने टेंडर जारी किया था। बीईएमएल ने एक्सचेंजों को जानकारी दी, प्रत्येक कार की कीमत रू. 27.86 करोड़ है और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रू. 866.87 करोड़ है। इसमें डिज़ाइन खर्च, एक बार की विकास लागत, गैर-आवर्ती शुल्क, और जिग्स, टूलिंग, फिक्स्चर, और टेस्टिंग सुविधाओं की लागत शामिल है।

अदाणी ग्रीन की डॉलर बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की योजना रद्द

नईदिल्ली। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली अदाणी ग्रुप की कंपनी, अदाणी ग्रीन एनर्जी ने डॉलर बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मीडिया ने मंगलवार देर रात को इस मामले से परिचित दो बैंकिंग सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों ने कंपनी की अपेक्षा से अधिक यील्ड पर बोली लगाई, जो कंपनी के लिए स्वीकार्य नहीं थी। इस कारण कंपनी ने धन जुटाने की योजना को रद्द कर दिया। एक बैंकर के मुताबिक, प्रारंभिक मार्गदर्शन के तहत 20 साल की परिपक्वता अवधि के लिए 7 प्रतिशत यील्ड की पेशकश की गई थी। बैंकर ने कहा, कुछ निवेशक उच्च यील्ड की मांग कर रहे थे, जो कंपनी के हिसाब से सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस सौदे को रद्द करने का निर्णय लिया। इस संबंध में रॉयटर्स के भेजे गए ई-मेल का अदाणी ग्रीन एनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

एलएंडटी को आगरा मेट्रो के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला

नईदिल्ली। इंजीनियरिंग व निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को आगरा मेट्रो के डिजाइन तथा निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसीएल) से एक ''बड़ा'' ठेका मिला है। कंपनी ने बुधवार को बीएसई को दी सूचना में बताया, यह ठेका एलएंडटी के भारी नागरिक बुनियादी ढांचे खंड को मिला है। एलएंडटी 1,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये के बीच के मूल्य के ठेके को बड़ा ठेका बताती है। कंपनी सूचना के अनुसार, उसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसीएल) से आगरा मेट्रो प्रथम चरण लाइन-2 के डिजाइन तथा निर्माण के लिए ठेका मिला है। एलएंडटी के पूर्णकालिक निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (आधारभूत संरचना) एस. वी. देसाई ने कहा, '' एलएंडटी शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के अवसर

डॉ. जयंतीलाल

अब भारत को आर्थिक दुनिया के एक उभरते सितारे के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख को दर्शाता है। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत भारत की आर्थिक स्थिति से भी मिल रही है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के साथ मित्रता के नये अध्याय दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा एवं भारतीय बाजार में मौके बढ़ा रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि विकास और बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश-दुनिया के कारोबारियों और निवेशकों के लिए मौकों का नया द्वार खोल रही हैं।

हाल में लाओस के वियनतियाने में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद आसियान देशों द्वारा जारी बयान के मुताबिक ये देश इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रमकता से असहज और परेशान हैं तथा वे भारत के साथ आर्थिक व सुरक्षा संबंधों का नया दौर आगे बढ़ायेंगे। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रोत्साहन उपायों के बावजूद चीनी अर्थव्यवस्था सुस्त होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वर्ष 2024 में चीन की विकास दर घटकर चार फीसदी होने का अनुमान है, जबकि भारत की विकास दर 6.3 फीसदी से अधिक रहेगी। वस्तुत: भारत के पास उपभोक्ताओं का उभरता हुआ विशाल बाजार, युवाओं में जबरदस्त ढंग से आगे बढ़ने की ललक, उद्यमिता की भावना और सुधार का रवैया वैश्विक संघर्ष तथा चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए नये अवसरों का आधार हैं। बीते चार अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा था

कि रूस-यूक्रेन और इस्त्राइल-ईरान युद्ध की अनिश्चितता के बीच भी दुनिया का भारत पर असाधारण आर्थिक विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरों में यह युग भारत का युग है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ग्लोबल फिनटेक एडाप्शन के मामले में पहले, इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में दूसरे, स्टार्टअप के मामले में तीसरे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज जैसी वैश्विक एजेंसियां आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को दुनिया की सबसे विश्वसनीय और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ निवेश के पसंदीदा देश के रूप में देख रही हैं।

यद्यपि इस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के विस्तारित होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर बढ़ रहा है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास और तेज विकास के मद्देनजर देसी उद्यमियों के साथ वैश्विक उद्यमियों के लिए भी बढ़ते अवसरों का परिदृश्य उभरता दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि हाल में दुनिया की ख्याति प्राप्त वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि सितंबर 2024 के दौरान भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए खुद को निवेश की पसंदीदा जगह बना लिया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी नयी रिपोर्ट में कहा है कि भारत आर्थिक विकास, विदेशी निवेश और नयी तकनीकों के उपयोग की ऊंची संभावनाओं वाला देश है। अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में अमेरिकी कंपनियों की वैश्विक निवेश पसंद में भारत का दूसरा स्थान है। इस समय चीन अमेरिकी निवेशकों की प्राथमिकता खोता जा रहा है। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के माहौल में इस समय चीन में कार्यरत 12 लाख करोड़ रुपये निवेश वाली 50 अमेरिकी कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों में से 15 कंपनियां भारत में निवेश की तैयारी कर रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विगत 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करने वाली 15 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बहुआयामी क्षेत्रों में दुनिया के लिए अपार आर्थिक मौके हैं।

रायपुर दक्षिण उपचुनाव की तैयारी में जुटे भाजपाई : संगठन महामंत्री साय और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ली बैठक

भाजपा की रिकॉर्ड जीत के लिए कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. आज एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आवश्यक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संयोजक श्यामबिहारी जायसवाल ने भाजपाइयों को मार्गदर्शन देते हुए उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा की रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजा जाएगा. भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बैठक ली, जिसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे. प्रदेश संगठन महामंत्री साय ने बैठक में मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर की जानकारी ली एवं बैठक में आए सभी लोगों का मार्गदर्शन किया. संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि जनता का जो विश्वास हम पर लगातार कायम है वह विश्वास हमें फिर प्राप्त करना है. इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संयोजक श्यामबिहारी जायसवाल ने भी चुनाव के मद्देनजर आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए आगामी उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा की रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया. बैठक में भाजपा संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोनी, दक्षिण विधानसभा प्रभारी विजय केसरवानी जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ,महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर, सत्यम दुबा, मोहन एंटी मंत्री अकबर अली, भाजपा मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल सच्चिदानंद उपासना सुभाष तिवारी जेपी शर्मा मिर्जा एजाज बाग मीनल चौबे सरिता वर्मा सरिता दुबे मनोज वर्मा मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा मुकेश पंजवानी सालिक ठाकुर प्रवीण दौवड़ा उपस्थित थे.

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अदानी के संरक्षक और राजस्थान सरकार के पोषक की तरह काम कर रही है: डॉ महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने भाजपा विष्णुदेव सरकार पर कोल खनन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अदानी के संरक्षक एवं राजस्थान सरकार के पोषक की तरह काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने कहा कि, विधानसभा में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन करके हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा एवं केते एक्सटेंशन नाम की नई कोयला खदानें खोलने का काम पुलिस संरक्षण में कराया जा रहा है।राजस्थान की कोयले की पूरी आवश्यकता पहले से चालू खदान, पी.ई.के.बी. से पूरी हो रही। नए खदान की जरूरत नहीं है, 2022 में कांग्रेस सरकार ने केंद्र को पत्र लिख कर परसा कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करने की मांग की थी कांग्रेस सरकार के रहते 16 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भी शपथ पत्र दाखिल कर परसा या केते एक्सटेंशन या किसी अन्य खदान की आवश्यकता को गलत बताया था। नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत का कहना है कि, आदिवासी होते हुए भी वे आदिवासी क्षेत्रों को उजाड़ने और हसदेव अरण्य क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण जंगल को काटने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि राजस्थान की सारी कोयला आवश्यकता पहले से चालू खदान से पूरी हो रही है और नए खदान की कम से कम 18 साल कोई आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को हसदेव अरण्य क्षेत्र में चार कोल ब्लॉक आवंटित है।परसा ईस्ट और केते बासन खदान को मिलाकर जो खदान बनाई गई है पीईकेबी इसकी उत्पादन क्षमता 21 मिलियन टन की जा चुकी है। पिछले साल ही वहां 18 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ।

छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री

रायपुर। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज पारंपरिक वेशभूषा एवं परिधानों के साथ विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पार्स्ट से किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वनकर्मियों की अहम भूमिका होती है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में वनबल के कर्मचारी हिस्सा लेते है। इसके लिए वन कर्मियों का शारीरिक रूप से चुस्त-दूरूस्त रहना जरूरी है। वनकर्मियों के लिए खेल का विशेष महत्व है, खेल से एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने माता कौशल्या की धरती में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए वन विभाग की मेहनत काबिले तारीफ है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत वर्ष 1992 में हुई थी। धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस खेल में कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं अपितु केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, राजधानी रायपुर का यह स्टेडियम लघु भारत के रूप में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश मे खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। वनरक्षक से लेकर विभाग के अधिकारी भी शामिल हो रहे खिलाड़ी का वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अहम भूमिका होगी।

बिहार के वन मंत्री डॉ. प्रेमकुमार ने कहा कि वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं जागरूकता लाने के लिए हमे आगे आना होगा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत आंध्रप्रदेश के हैदराबाद से हुई थी। इस बार यह आयोजन प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। डॉ. कुमार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकानाएं दी। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल प्रातिभाओं का बढ़ाने के साथ-साथ उनका सम्मान भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पांच दिन तक चलने वाला यह आयोजन वनों के संरक्षण पर आधारित है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हो रहा है। उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित खिलाड़ियों के साथ-साथ उपस्थित जनसमुदाय को पेड़ और वन्यप्राणी के सरंक्षण के लिए प्रेरित किया। आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य न केवल सरकार का है अपितु सभी की नैतिक जवाबदारी है। अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के भारतीय कप्तान श्री सूर्य कुमार यादव ने जय जोहर के उद्घोधन से अपनी बात रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों ओर हरियाली है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के कैरियर में अनुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वनों को हराभरा रखने और खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए इस आयोजन के लिए बधाई दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की मेजबानी में चार साल बाद 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में 26 खेल की 300 विधाओं में प्रतियोगिताएं होगी। यह प्रतियोगिता 16 से 20 अक्टूबर तक राजधानी के 16 अलग-अलग खेले मैदानों में होगा। इसमें देशभर से 2920 खिलाड़ी भाग लेंगे। जिसमें 2331 पुरुष और 585 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ के 268 खिलाड़ी 12वीं बार ओवरऑल चैम्पियनशिप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हमारी टीम अब तक 11 बार ओवरऑल चैम्पियनशिप का खिताब जीत चुकी है। प्रतियोगिता प्रारंभ के पूर्व विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों द्वारा किए गए मार्च पार्स्ट में छत्तीसगढ़ प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु तथा असम और गुजरात के दल को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रामप्रसाद, विधायकगण राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पद्मश्री अनुज शर्मा, सचिव (वन) भारत सरकार की श्रीमती लीना नंदन, वन महानिदेशक भारत सरकार जितेन्द्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक एवं प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी श्रीमती शालिनी रैना सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और आम लोग उपस्थित थे।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा: डॉ टोपलाल वर्मा

रायपुर। पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर त्रिशताब्दी जयंती आयोजन समिति रायपुर महानगर की ओर से बुधवार (16 अक्टूबर,2024) को डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़,मुख्य वक्ता डॉ टोपलाल वर्मा माननीय संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत,अध्यक्षता डॉ सी एल देवांगन प्राचार्य डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर,श्रीमती विशिष्ट अतिथि प्रियदर्शिनी दिव्य जी थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर सामाजिक परिवर्तन की वाहक थीं। उन्होंने घुमन्तू समाज के उत्थान के लिए काम किया। भीलों के लिए भील कौड़ी की शुरुआत की और उन्हें कृषि के लिए प्रेरित किया। वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थीं। उन्होंने महिलाओं की सेना का गठन किया। राज्य की आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए आर्थिक सुधार किये।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा नेता सोलंकी के पास लाखों रुपए आया कहां से इसकी जांच की जाये?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का काला खेल तेजी से बढ़ा है। भाजपा के बड़े नेता से लेकर मंडल स्तर तक के नेता अवैध उगाही में लगे हुए हैं। भानुप्रतापपुर के मंडल अध्यक्ष बेरोजगार आकाश सोलंकी अपनी कार में लाखों रुपए की नोट की गड्डी रखकर रील बनाते हैं। आखिर बेरोजगार युवक के पास इतना पैसा आया कहां से राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और आयकर विभाग भी संज्ञान में ले। जबकि आम नागरिक अपने साथ 2 लाख रु से अधिक की नगद राशि रखकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या भाजपा नेताओं को लाखों रुपए रखकर सफर करने की विशेष छूट दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद हंसो को दाना नहीं और कौआ मोती खा रहे वाली कहावत चरितार्थ हो रहा है। बेरोजगारो को न रोजगार मिल रहा है, न बेरोजगारी भत्ता और भाजपा के बेरोजगार नेता लाखों रूपये की नोटो की गड्डी लेकर रील बना रहे है। मुछों में ताव देकर प्रदेश के बेरोजगार युवा को चिढ़ा रहे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते हैं कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो बनाया गया है जबकि भाजपा नेता आकाश सोलंकी स्वीकार कर रहे हैं कि नोटों के साथ रील उन्होंने बनाया है।

आवश्यक दवाओं के कीमत में अनुचित बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है

रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा आवश्यक दवाओं की कीमत में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का फोकस केवल मुनाफाखोरी में है। दवा कंपनियों को अनाप शनाप वसूली की छूट और आम जनता को लुटने की अनुज्ञप्ति जन विरोधी भाजपा की सरकार में मिली हुई है। एक तरफ देश की जनता मोदी निर्मित महंगाई, बेरोजगारी और घटती आमदनी से परेशान है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संरक्षण में तमाम खाद्य पदार्थों, पैट्रोलियम उत्पात से लेकर अब दवाओं में भी जमकर मुनाफाखोरी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि ड्रग प्राइज रेगुलेटरी द्वारा भारी भरकम मूल्य वृद्धि को मंजूरी देने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दवा कंपनियों द्वारा दिए इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत जनता की जेब से डकैती करके चुकाया जा रहा है? या लूट की खुली छूट में भाजपा की हिस्सेदारी है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इससे पूर्व इसी साल अप्रैल 2024 में भी सैकड़ों दवाओं की कीमत में वृद्धि की गई थी।

धान खरीदी की तिथि कम करना सरकार की बदनीयती

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू किया जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 14 नवंबर से धान खरीदी के निर्णय से सरकार की नीयत में खोट साफ नजर आ रही है। सरकार 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी का निर्णय लिया है। इसका मतलब है पहले ही सरकार धान खरीदी 14 दिन कम करेगी। यदि शुरूआत देर से की जा रही है तो खरीदी की अंतिम तिथि को 15 दिन आगे बढ़ाना चाहिये। ताकि सभी किसानों का धान समर्थन मूल्य पर बिक सके। खरीदी अवधि कम करना भाजपा सरकार बदनीयती का प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की घोषणा के अनुसार 14 नवंबर से 31 जनवरी तक कुल 75 दिन के अंदर धान खरीदी का लक्ष्य है, इसमें से 35 दिनों लगभग एक महिना से अधिक छुट्टी है, अर्थात मात्र 40 दिन ही सरकार धान खरीदी करेगी। मात्र 40 दिनों में 30 लाख से अधिक किसानों के धान की खरीदी संभव नहीं। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। रकबा बढ़ा है। पैदावार भी ज्यादा हुआ है। प्रति एकड़ खरीदी की लिमिट भी बढ़ी है, फिर खरीदी की अवधि कम करने का आधार क्या है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार इस वर्ष धान की खरीदी 3217 रू. में करे क्योंकि 3100 रू. भाजपा ने अपने चुनावी वायदे में कहा था।

झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू का राजधानी में नेटवर्क

रायपुर। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपना नेटवर्क फैला लिया है। रायपुर पुलिस द्वारा रिमांड पर लेकर की जा रही पूछताछ में साहू ने कई बड़े खुलासे किए हैं। रायपुर एसपी संतोष सिंह ने बताया कि राजधानी में अमन साहू का लोकल नेटवर्क सक्रिय है, और इसके कई लिंक पुलिस के सामने आए हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि तेलीबांधा और गंज थाने में दर्ज मामलों में अमन साहू से पूछताछ जारी है। पिछले दो दिनों से लगातार जांच चल रही है। उल्लेखनीय है कि रायपुर कोर्ट ने अमन साहू को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। सोमवार की रात कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया। शाम 4 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अमन साहू को झारखंड जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस टीमों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। अमन साहू को रायपुर में सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस में रखा गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

23 से रेल पटरी पर दौड़ेगी गया-एलटीटी-गया

रायपुर। रेल यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा गया एवं एलटीटी के बीच 22357/22358 गया-एलटीटी-गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई ट्रेन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुपरफास्ट ट्रेन गया से 22358 गया-एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के नंबर से एवं एलटीटी 22357 एलटीटी-गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के नंबर से चलेगी। 23 से रेल पटरी पर दौड़ेगी गया-एलटीटी-गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन गया से प्रत्येक बुधवार को 23 अक्टूबर से एवं इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी एलटीटी से प्रत्येक शुक्रवार को 25 अक्टूबर,से चलेगी। इस गाड़ी में एसी प्रथम-01, 02 एसी/।।-2, एसी/।।।-3, स्लीपर-09, सेकंड सिटिंग कोच- 6 तथा एसएलआर-2 सहित कुल 22 कोच के संरचना के साथ चलेगी।

आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक : कलेक्टर

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है तथा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। इस प्रक्रिया में राजनैतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी के सहयोग से रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया को सफ्लता पूर्वक संपन्न कर पाएंगे। उपनिर्वाचन 2024 के संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सिंह द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में ली गई। बैठक के दौरान आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई तथा आचार संहिता का आवश्यक रूप से पालन करने की अपेक्षा राजनीतिक दलों से की। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि नामांकन के समया किसी प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ या एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के भीतर नही आएंगे। मतदान के दिन प्रत्याशियों को केवल तीन वाहनों की संचालन की अनुमति होगी.एक स्वयं के लिए एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और एक कार्यकर्ताओं के लिए। इन वाहनों के लिए अनुमति पत्र सक्षम प्राधिकारी जारी करेंगे और यह अनुमति पत्र वाहनों के सामने शीशे पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को जातीय, धार्मिक विषयों से बचकर अपना प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वोट के लिए अपील करते समय धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नही किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति पर, भवन, भूमि अथवा परिसर पर झंडे,पोस्टर बैनर आदि उसकी पूर्वानुमति के बिना नही लगाएगा और न ही अपने समर्थको को ऐसा करने दें। अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर नहीं दी जायेगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में भी अस्थायी प्रचार कार्यालय की अनुमति नहीं दी जाएंगी। किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में ये किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकेंगे ।

साहसी बनेंगी कृषि विवि की छात्राएं: 17 से 19 तक स्वरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा लैगिंक उत्पीड़न शिकायत समिति, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मिशन साहसी (मेकिंग ऑफ फ्यिरलेस) के अन्तर्गत स्वरक्षा कार्यक्रम का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर, 2024 तक किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन थीम रानी अहिल्याबाई होल्कर, रानी दुर्गावती एवं झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के साहस से प्रेरणा लेते हुए विश्वविद्यालय की छात्राओं, महिला कर्मचारियों एवं उनके परिवार की महिलाओं को शारीरिक स्वरक्षा संबंधी तकनीकों का सजीव प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे किसी आकस्मिक घटना की स्थिति में इस कौशल का प्रयोग कर अपनी स्वयं की एवं अन्य महिलाओं की सुरक्षा कर सकें। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह श्रीमती ममता चंदेल के मुख्य आतिथ्य एवं विश्वविद्यालय की लैगिंक उत्पीड़न शिकायत समिति डॉ. आरती गुहे की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर, 2024 को प्रात: 10 बजे सम्पन्न होगा। इस अवसर पर डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं डॉ. जी.के. दास अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम में कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से बचाव हेतु स्वरक्षा की शारीरिक दांव पेंच एवं तकनीक का अंजली गिरी गोस्वामी अन्तर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी एवं सेकंड डेन ब्लेक बैल्ट द्वारा सजीव प्रशिक्षण तीन दिवस तक दिया जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.